पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

# आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 16-30 JUNE-2025

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070


# मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र कर के मोदी ने कहा, आपातकाल लाने वाले वाले हार गए

## बताया कि उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर अमानवीय अत्याचार हुए

नई दिल्ली (एजंसी) – पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है, वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई और आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो 'मन की बात' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि Emergency लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जॉर्ज फर्नांडीस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को



कठोर यातनाएं दी गईं। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया।' पीएम ने आगे कहा, 'उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है, वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई और आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 साल कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेंशा उन लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार 21 जून को दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं।' पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, 'लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी, भगवान शिव का धाम। हिन्दू, बौद्ध, जैन, हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा भी देखी है।'

# आरएसएस का नकाब फिर उतरा; उसे संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए-राहुल गांधी

## जयराम रमेश भी हुए हमलावर

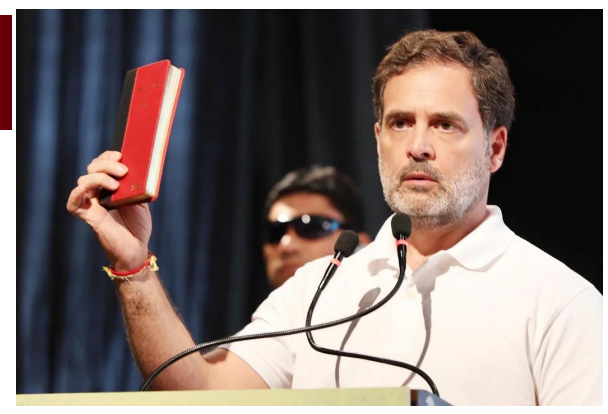

नई दिल्ली (रमन कुमार) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (ञ्स्स्) पर शुक्रवार को निशाना साधा। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने संबंधी बयान दिया। इसे लेकर राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। उसे संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है।'



राहुल गांधी ने आरोप लगाया, 'आरएसएस–भाजपा को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है।' कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस ये सपना देखना बंद करे क्योंकि उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया, 'हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा।' आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था, 'बाबासाहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए।' उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। होसबोले ने कहा, 'इसलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इसने 30 नवंबर 1949 के बाद से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और इसके निर्माण में शामिल अन्य लोगों पर निशाना साधा। आरएसएस के अपने शब्दों में संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था।'

# बीजेपी की सरकार ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी-केजरीवाल

नई दिल्ली (एजंसी) आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन के विरोध में जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया. इसमें पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह शामिल हुए. इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.



अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की सरकार ने झुग्गियां तोड़कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी. जो झुग्गी में रहते हैं, वे आसपास ही नौकरी करते हैं. लेकिन झुग्गी टूटने से रोजगार चला जाता है. इन्होंने एक तरह से आपको खौलते हुए तेल में डाल दिया है. केजरीवाल ने कहा, %चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी, वहां मकान... लेकिन उसका मतलब यह था कि जहां झुग्गी, वहां मैदान... मोदी की गारंटी फर्जी और नकली है. मोदी की गारंटी झूठी है. चुनाव से पहले इनके नेता आपके घरों में आकर सोते थे. मैंने कहा था कि इनके नेता आपकी झुग्गियां देखने के लिए आ रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी और भगा दिया तो काम कैसे चलेगा।

# मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद होगी

## केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दी मूंग और उड़द खरीदी की मंजूरी

एसके सक्सैना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बैठक कर मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द तथा उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के तहत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ संवाद भी किया और नेफेड, एन.सी.सी.एफ. व राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार करने तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य हितधारकों के साथ बैठक के उपरांत मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग तथा ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। श्री शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा




वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित में सरकार किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा। अधिकारियों को दिशा–निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकतम व कारगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं की जाएं। आवश्यकता हो तो खरीद केंद्रों की संख्या में भी इजाफा करें व उचित और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीद सुनिश्चित करें। श्री शिवराज सिंह चौहान ने भंडारण को लेकर मिल रही अनियमितताओं की शिकायत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों व कृषि मंत्रियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रयास करने की बात कही। श्री शिवराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में हरसंभव काम करेगी। बैठक में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

# शिक्षा क्षेत्र को गति देने के लिए लीक से हटकर कदम उठा रहे हैं-मुख्यमंत्री भगवंत मान

## नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को किया सम्मानित. शिक्षा को सभी समस्याओं की एकमात्र दवा बताया

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार पंजाब में शिक्षा क्षेत्र को प्रगति देने के लिए लीक से हटकर कदम उठा रही है। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन क्रांतिकारी कदमों से शिक्षा क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है, जिसके चलते आज पंजाब के छात्र प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पंजाब के 509 सरकारी स्कूलों के छात्रों ने प्रतिष्ठित नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, उद्योग, खेल, रोजगार और नशा उन्मूलन, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने % युद्ध नशों विरुद्ध卐% के रूप में एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशा





तस्करी में शामिल दोषियों को सख्ती से सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और नशे की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से यह सफलता हासिल की है और अब यह छात्र पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा 70 वर्षों से फैलाई गई अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मौजूदा सरकार ने अपने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण राज्य के अनेक युवाओं की आयु सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित सीमा से पार हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकारी स्कूलों के माध्यम से माता–पिता के सपने साकार हो रहे हैं, जो अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ राजनीतिक नेताओं के लिए चुनाव लड़ने की कोई आयु सीमा नहीं है, वहीं सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित उस भवन का भी विशेष उल्लेख किया, जहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि यह भवन हजारों युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्रों का साक्षी बना है, इसलिए इसे %नियुक्ति पत्र भवन% कहा जा सकता है। उन्होंने गर्व से कहा कि पंजाब सरकार अब तक 54,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियाँ प्रदान कर चुकी है। यह राज्य के लिए शुभ संकेत है कि अब पंजाब प्रवासी युवाओं की वापसी का साक्षी बन रहा है, क्योंकि अब सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध होने के कारण युवा विदेशों से लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही है, जिससे अब युवाओं का राज्य सरकार पर विश्वास बढ़ा है और वे विदेश जाने की सोच छोड़कर सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेहनती और संघर्षशील पंजाबी हर स्तर पर अग्रणी रहे हैं और पंजाब के पास उपजाऊ भूमि और साहसी लोगों की संपत्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण कई होशियार युवा विदेशों में जा बसे। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा परिस्थितियाँ बदलने के साथ ही अब बड़ी संख्या में छात्र सरकारी नौकरियों में शामिल होकर राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सकारात्मक बदलाव के तहत अब सरकारी स्कूलों में भी माता–पिता शिक्षक मीटिंग्स (पी.टी.एम.) का आयोजन किया जा रहा है, जो पहले केवल निजी स्कूलों तक ही सीमित थीं। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन पहल है, जिसके माध्यम से माता–पिता और शिक्षकों के बीच विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर बेहतर तालमेल स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है और इसे और अधिक गति देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य सरकार ने जनता के लिए आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना भी शुरू की है, ताकि छात्रों में पढ़ने की रुचि बढ़े। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों को वाई–फाई, सोलर पावर, डिजिटल एनालॉग और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पुस्तकालयों में विश्व स्तर की साहित्यिक पुस्तकों के साथ–साथ पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों के सीखने के अनुभव को और बेहतर बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुस्तकालयों में दुर्लभ और अनमोल पुस्तकों का भंडार है, जो पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

# पंजाब में लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं केजरीवाल, इंदिरा के आपातकाल की याद ताज़ा-चुग

मनदीप कौर

लुधियाना / चंडीगढ़–भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर लुधियाना में आयोजित जिला गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि–卐25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट की वजह से नहीं, बल्कि सत्ता लोलुपता में उस वक़्त की कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा संविधान के खिलाफ रची गई साजिश थी। यह न्यायपालिका द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सत्ता में बने रहने की बौखलाहट थी। चुग ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र को पल भर में तानाशाही में बदल दिया। 卐जिस संविधान की शपथ ली थी, उसी को कुचल दिया गया। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, न्यायपालिका को दबा दिया गया, और विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। उन्होंने बताया कि संविधानिक पद न रखने वाले संजय गांधी ने उस दौर में देश चलाया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह जैसे विपक्षी नेता बिना मुकदमे के जेल में बंद कर दिए गए। जस्टिस एच.आर. खन्ना जैसे निष्पक्ष न्यायाधीश को उनके फैसले की सजा दी गई। चुग ने कहा कि वर्त्तमान की गाँधी परिवार की परिक्रमावादी कांग्रेस ने प्रेस काउंसिल को भंग कर, सोशल मीडिया पर 'डिजिटल आपातकाल' थोप कर, और झूठ फैलाने वालों को



संरक्षण देकर यह साबित कर दिया कि वह आज भी वैसी ही है। 卐संस्थाओं को बंधक बनाना, परिवारवाद को लोकतंत्र पर थोपना और विपक्ष की आवाज़ को देशद्रोह बताना–यह सब उस तानाशाही मानसिकता का ही विस्तार है। आप सरकार पर हमला करते हुए, चुग ने कहा–卐भगवंत मान की सरकार चंडीगढ़ से नहीं, केजरीवाल के घर से उनके करीबियों से चलती है। बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। यह केजरीवाल का 'डंडा तंत्र' है–जिसमें विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं–एक आपदा तो दूसरी कापदा। दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है और लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पंजाब की जनता इन दोनों को पूरी तरह नकार देगी, क्योंकि जनता अब इनके झूठ और पाखंड से ऊब चुकी है।

## संपादकीय

# अनुशासन क्या है?

अनुशासन लैटिन शब्द डिसिपुलस से निकला है जिसका शाब्दिक शब्दिक अर्थ सिखाना या मार्ग दर्शक करना है। अनुशासन का अर्थ नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करना,अपने कार्यों को नियंत्रित करना इत्यादि। उदाहरणतय नियमित समय पर कार्य करना,लक्ष्यों को केंद्रित करना,दूसरों सम्मान एवं शिष्टाचार का पालन करना। अनशासन का संधि विच्छेद अनु+शासन

जिसका स्वयं पर शासन करना तथा उसके अनुसार चलना। उदेश्य:= अनुशासन व्यक्तिगत जीवन में अति अनिवार्य है। अनुशासन के बिना जीवन पशु समान है। अनुशासन हीनता की तुलना एक किश्ती बिना चप्पू या पोस्ट कार्ड पाने वाले के पते यानी एड्रेस के बिना होता है। किसी परिवार ,संगठन, संस्थानों,कार्यालयों की कार्यकुशलता हेतु अनुशासन अति अनिवार्य है। अनुशासित रहने हेतु कुछेक महत्वपूर्ण तरीकों का पालन आवश्यक है।समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारित,आत्म नियंत्रण,अच्छी आदतें एवं सकारात्मक सोच। इस अनुशासन मानव जीवन में स्थिरता एवं संतुलन बनाए रखना में सहायक होता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। अनुशासन को अंग्रेजी इंग्लिश भाषा में डिसीपलिन [DISCIPLINE यानी 10 अक्षरों को मिला कर बना है] यदि प्रत्येक अक्षर का मुलांक निकाल जोड़ कर देखें तो 100 आता है।

उदाहरणतय:= D=4, I=9, S=19, C=3,I=9, P=16, L=12, I=9, N=14 ,E=5 कुलयोग =100 आता है। इस हमें 100 प्रतिशत अनुशासन कायम रखना है।

# एनएसएसओ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने मनाया 19वां सांख्यिकी दिवस

पंकज

चंडीगढ़, अर्थशास्त्र, योजना एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के अतुलनीय योगदान की स्मृति में एनएसएसओ (एफओडी) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने 29 जून 2025 को मिनी हॉल, केंद्रीय सदन, सेक्टर–9, चंडीगढ़ में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष है। समारोह का उद्घाटन उप महानिदेशक श्री दीपक मेहरा ने किया, जिन्होंने प्रो. महालनोबिस के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि, प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक (सेवानिवृत्त) श्री पवित्र सिंह ने भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में प्रो. महालनोबिस के योगदान और दैनिक जीवन में सांख्यिकी की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। श्री आर.के. मोर, अतिरिक्त निदेशक, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ऐतिहासिक यात्रा साझा की, जबकि वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री वासुदेव शर्मा ने डेटा संग्रहण के दौरान अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रो. महालनोबिस को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन और पोस्टर प्रदर्शनी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की। यह कार्यक्रम न केवल सांख्यिकी के महत्व को रेखांकित करने में सफल रहा, बल्कि राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

# भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम - डी.ई.ओ. कार्यालय का क्लर्क शिक्षक से दूसरी किस्त के 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

रमन कुमार

**आरोपी पहले भी ले चुका है 10,000 रुपए रिश्वत**

चंडीगढ़, पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी सख्त मुहिम के दौरान आज जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंट्री), मालेरकोटला के कार्यालय में तैनात क्लर्क विकास जिंदल को एक शिक्षक से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी क्लर्क ने जिला मालेरकोटला के गांव बागड़ियां के शिकायतकर्ता शिक्षक से डी.ई.ओ. कार्यालय में उसके बकाया भत्ते जारी करने के बदले में कुल 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि उक्त क्लर्क पहले ही उससे 10,000 रुपए रिश्वत ले चुका है और अब बाकी की रकम की मांग कर रहा है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, पटियाला रेंज की विजीलेंस टीम ने जाल बिछा कर उक्त क्लर्क को दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत की रकम के रंग लगे हुए नोट मौके पर ही बरामद कर लिए गए। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से विजीलेंस ब्यूरो ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिले तो वे इसे हेल्पलाइन नंबरों या आधिकारिक चैनलों के माध्यम से तुरंत साझा करें। साथ ही, ब्यूरो ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

# पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कर रही है बड़े प्रयास- डॉ. बलजीत कौर

**पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान; 2 लाख 70 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य**

एसके सक्सैना

चंडीगढ़, 28 जून–मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के उत्थान के लिए दिन–रात काम कर रही है, वहीं अनुसूचित जाति के बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार विशेष प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। अधिक जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 70 हजार अनुसूचित

जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 575 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया था और राज्य सरकार की ओर से 266.57 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई थी। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जल्द ही डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देकर यह प्रयास कर रही है कि ये बच्चे पढ़–लिखकर आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन वर्गों के साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है, उनके योग्य बच्चे आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाएं। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हजारों एस.सी. विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज उच्च पदों पर नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में तथा अपने व्यवसायों में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक योग्य विद्यार्थी तक अवश्य पहुँचाया जाए जिसे इस योजना की वास्तव में जरूरत है। साथ ही, उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस योजना को पूरी पारदर्शिता, सुचारु और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए।

# 8,000 रुपए रिश्वत लेते सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

मनदीप कौर

चंडीगढ़, –पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के दौरान, जिला फाजिल्का के थाना अमीर खास में तैनात सब–इंस्पेक्टर (एस.आई.) रवीपाल को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंध में आज यहां जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी फिरोजपुर जिले के गुरूहर सहाए निवासी की शिकायत के आधार पर की गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया था कि आरोपी एस.आई. ने हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन का जवाब तैयार करने और जमा करवाने तथा शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज पुलिस केस से संबंधित चार्जशीट जिला अदालत में पेश करने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर उक्त पुलिस कर्मचारी को दो सरकारी गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना, फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

# पाकिस्तान आई. एस. आई. को फ़ौज से सम्बन्धित संवेदनशील डाटा लीक करने के लिए एक फ़ौजी जवान और उसका साथी गिरफ़्तार

पंकज

**आई. एस. आई. हैंडलर राणा जावेद के सीधे संपर्क में था जम्मू में तैनात फ़ौजी गुरप्रीत सिंह; पैन ड्राइव के द्वारा भेजता था खुफ़िया जानकारी–डीजीपी गौरव यादव**

चंडीगढ़/ अमृतसर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान बड़ी जासूसी–विरोधी कार्यवाही करते हुये अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने भारतीय फ़ौज के एक जवान और उसके सहयोगी को फ़ौज से सम्बन्धित संवेदनशील डाटा पाकिस्तान की इंटर– सर्विसिज इंटेलिजेंस ( आई. एस. आई.) को लीक करने शक में गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने रविवार को यहाँ दी। गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ

गोपी फ़ौजी निवासी धारीवाल, अमृतसर, जो मौजूदा समय भारतीय फ़ौज के जवान के तौर पर जम्मू में तैनात है और उसके साथी साहिल मसीह उर्फ शाली, जो कि अमृतसर के धारीवाल का रहने वाला है, के तौर पर हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गुरप्रीत सिंह पाकिस्तानी आई. एस. आई. के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में था और यह शक है कि वह पैन ड्राइव के द्वारा संवेदनशील और खुफ़िया जानकारी सांझी करता था। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में शामिल मुख्य आई. एस. आई. हैंडलर की पहचान राणा जावेद के तौर पर हुई है। डीजीपी ने कहा कि गिरफ़्तार किये गए दोनों मुलजिमों के कब्ज़े में से वर्चुअल नंबरों वाले दो मोबाइल फ़ोन बरामद किये गए हैं, जिनका प्रयोग कथित तौर पर आईएसआई के गुर्गों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता था। उन्होंने कहा कि जासूसी–दहशतगर्दी के व्यापक नैटवर्क को जड़ से तबाह करने और इस मामले में सभी सहयोगियों की पहचान करने के लिए और जांच की जा रही है। अन्य विवरण सांझा करते हुये सीनियर सुपरडैंट आफ पुलिस ( एस. एस. पी.) अमृतसर ग्रामीण मनिन्दर सिंह ने कहा कि मुलजिम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फ़ौजी 2016 में फ़ौज में भर्ती हुआ था और यह अंदेशा है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये पैन ड्राइव और डिस्क द्वारा फ़ौज की खुफ़िया जानकारी जुटायी और पाकिस्तान आईएसआई को लीक की। उन्होंने कहा कि जासूसी नैटवर्क को कथित तौर पर धारीवाल के एक दुबई–आधारित नशा तस्कर, अर्जुन ने पाँच महीने पहले गुरप्रीत को आईएसआई के गुर्गों के साथ रूबरू करवाया था। उन्होंने बताया कि कि उस समय से, गुरप्रीत पहले से निर्धारित ड्राप स्थानों का प्रयोग करके आईएसआई को फ़ौज का संवेदनशील डाटा सक्रियता से भेजने में लगा हुआ था।

# मोहिंदर भगत ने बागवानी विभाग की प्रगति की समीक्षा की, किसानों को समय पर सब्सिडी वितरण पर जोर दिया

रमन कुमार

चंडीगढ़, –पंजाब के बागवानी मंत्री, श्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की

समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभाग की चल रही परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक के दौरान, बागवानी सचिव, श्री मोहम्मद तैय्यब ने मंत्री को विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत हुई प्रगति से अवगत कराया। श्री तैय्यब ने मुख्य उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी साझा की। श्री भगत ने किसानों को सब्सिडी के पारदर्शी और समय पर वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे बिना किसी देरी के सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। उन्होंने बागवानी से संबंधित सभी पहलों को शीघ्र पूरा करने और जमीनी स्तर पर किसानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करने तथा किसानों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने हेतु लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बागवानी को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में कृषि विविधीकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री भगत ने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि चल रही सभी प्रगति योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

# पंजाब में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम; नाबालिग समेत बी के आई मॉड्यूल के तीन सदस्य गिरफ्तार

कैप्टन सुभाष चंदर

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा–निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही विशेष मुहिम के दौरान, पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशों पर यूके आधारित निशान सिंह द्वारा संचालित, पाकिस्तान–आई एस आई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी के आई) के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहजपाल सिंह, विक्रमजीत सिंह (दोनों निवासी रामदास, अमृतसर) और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। यह कार्रवाई स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस एस ओ सी ) मोहाली द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। डी जी पी गौरव यादव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, एक आधुनिक 9एम एम ग्लॉक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह गिरोह अमृतसर क्षेत्र में पुलिस संस्थानों पर हमले और टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इस गिरफ्तारी से एक बड़ी आतंकवादी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है, जिससे अनगिनत मासूम जानें बचाई जा सकी हैं। डी जी पी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व बरामदगी की संभावना है। ए आई जी, एस एस ओ सी एसएएस नगर रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी सहजपाल सिंह ने खुलासा किया कि वह अमृतसर के गांव पैरेवाल के रहने वाले लवप्रीत सिंह उर्फ लव (जो फिलहाल फिरोजपुर जेल में बंद है) के निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि सहजपाल के खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने लवप्रीत सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर एस एस ओ सी, एसएएस नगर में लाकर पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि लवप्रीत ने सहजपाल को हथियार और विस्फोटक सामग्री हासिल करने के निर्देश दिए थे और सहजपाल ने इस कार्य में अपने साथी विक्रमजीत सिंह को भी शामिल किया था। उल्लेखनीय है कि लवप्रीत सिंह एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह गिरोह के सदस्यों को लामबंद करने और निर्देश देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। ए आई जी ने बताया कि बरामद हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल टारगेट किलिंग और विस्फोटक हमलों के लिए किया जाना था और विस्फोट करने की जगह और समय बाद में विदेश स्थित संचालकों द्वारा बताया जाना था। बरामद ग्लॉक पिस्तौल का इस्तेमाल विरोधी गिरोह के सदस्यों की टारगेट किलिंग में किया जाना था। इस संबंध में एफ आई आर नंबर 09, दिनांक 22–04–2025, थाना एस एस ओ सी , एसएएस नगर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी), 25(7) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत दर्ज की गई है।

**पुलिस टीमों ने दो हैंड ग्रेनेड और एक ग्लॉक पिस्तौल की बरामदगी कीच, आतंकी मॉड्यूल, हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशों पर यूके आधारित निशान सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा था–डी जी पी गौरव यादव**

# ए.एस.आई. और पंचायत सदस्य के खिलाफ 20,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज

एसके सक्सैना

**पंचायत सदस्य, जो बिचौलिया था, गिरफ्तार**

चंडीगढ़, –पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा राज्य में जारी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान ए.एस.आई. (एल.आर.) अवतार सिंह, थाना सिटी रामपुरा, जिला बठिंडा और राजदीप सिंह, पंचायत सदस्य, गांव रामपुरा के विरुद्ध 20,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सह–अभियुक्त राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव धौला, जिला बरनाला निवासी शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह सामने आया कि संबंधित थाने में शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता को लाभ पहुँचाने के बदले पुलिस कर्मचारी ने पंचायत सदस्य राजदीप सिंह के माध्यम से शिकायतकर्ता से 40–50 हजार रुपये की मांग की थी और 20,000 रुपये की रिश्वत ली थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सह–अभियुक्त पंचायत सदस्य राजदीप सिंह को विजिलेंस ब्यूरो, बठिंडा यूनिट द्वारा गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। संबंधित ए.एस.आई. की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

**आज तक आमने सामने**
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

**आवश्यक सूचना**

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञिापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

# युद्ध नशे के विरुद्ध-बस्ती गुजां में नशा तस्कर का अवैध निर्माण ध्वस्त

## कमिश्नरेट पुलिस ने शहर से नशा खत्म करने की वचनबद्धता दोहराई





**एस. के. सक्सैना**

जालंधर, नशे के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए नगर निगम जालंधर ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के साथ मिलकर शनिवार को बस्ती गुजां में कुख्यात नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ' युद्ध नशे के विरुद्ध ' के तहत अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए चल रहे अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा बनाए गए अतिक्रमण वाले ढांचे को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस सहायता प्रदान की। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि नगर निगम को कुख्यात नशा तस्कर विशाल उर्फ ??चूचा द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी। जिस पर नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कब्जे वाले ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे नशा तस्करों को सख्त संदेश गया कि जालंधर शहर में नशे से संबंधित गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एन.डी.पी.एस.) एक्ट के तहत कुल चार मामले दर्ज है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'युद्ध नशे के विरुद्ध ' अभियान लगातार गति पकड़ रहा है और अधिकारी नशे से संबंधित अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पहले भी ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें फिल्लौर क्षेत्र, धनकिया मोहल्ला, रामा मंडी, गढ़ा, भार्गव नगर और लोहियां में नशा तस्करों से संबंधित अवैध संरचनाओं को गिराना शामिल है। कमिश्नर पुलिस ने समाज से नशे के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए नागरिकों से जालंधर को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय सहयोग करने की अपील भी की।

# पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की, मत्था टेका

**मनदीप कौर**

जालंधर, पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने जालंधर वेस्ट हलके, करतारपुर, आदमपुर, अलावलपुर समेत अलग अलग इलाकों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान सुशील रिंकू ने मत्था टेका और अरदास की। जालंधर में काला संघिया रोड स्थित हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमत–तुला–आलिया नक्श बंद चिश्ती जी के सालाना मेला में पहुंचकर सुशील रिंकू ने मत्था टेका। गद्दी नशीन साईं विनोद शाह जी हंस ने रिंकू को सम्मानित किया। इसके अलावा जालंधर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बाबा रूलिआ शाह जी के सालाना मेला में रिंकू ने शिरकत की, मुख्य सेवादार दीपा हीर ने रिंकू को सम्मानित किया। जालंधर वेस्ट हलके में स्थित रसीला नगर बस्ती दानिशमंदा में दरबार हजरत ख्वाजा बाबा पीर पठान शाह सिकंदर जी के सालाना मेला में सुशील रिंकू शिरकत की। यहां जै बाबा कालीवीर वेलफेयर सोसाइटी ने सुशील रिंकू का स्वागत किया। जालंधर वेस्ट हलके के काला संघिया रोड स्थित बस्ती शेख में मां वैष्णों देवी धमा सभा और बाबा कांता जी द्वारा करवाए गए वार्षिक जागरण में सुशील रिंकू बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हाजिरी लगाई और माता के भवन में मत्था टेका। जालंधर वेस्ट हलके के बलदेव नगर बस्ती दानिशमंदा में दरबार ताले मोल यकीन हजरत बाबा दोश मोहम्मद प्रबंध कमेटी के सेवादार रविहंस द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सुशील रिंकू ने हिस्सा लिया। अलावलपुर के मोहल्ला नवीपुर में महंत आशा रानी जी और महंत बिंदु जी की याद में आयोजित सालाना बरसी में सुशील रिंकू ने हाजिरी लगाई और महंतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्य सेविका महंत दीपिका जी ने सुशील रिंकू का स्वागत किया। आदमपुर में समूह दरबार पंजपीर कमेटी द्वारा आयोजित सालाना जोड़ मेला में पूर्व सांसद सुशील रिंकू मुख्य मेहमान के रूप में हाजिरी लगाई। करतारपुर के मोहल्ला चंदन नगर में स्थित इच्छाधारी बाबा बोहड़ शाह दी के सालाना मेला में सुशील रिंकू ने हाजिरी लगाई। इस दौरान सेवादार हरविंदर सिंह बाबा जी ने रिंकू को सम्मानित किया।

# भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर.पी. सिंह ने आपातकाल के काले दौर पर की प्रेस वार्ता

## कांग्रेस का आज भी मानना है कि इस देश की सत्ता पर केवल और केवल उनके परिवार का हक है–आर.पी सिंह

**पंकज**

जालंधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर,पी सिंह ने आज आपातकाल के काले दौर को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ,जालंधर के पूर्व मेयर एवं प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, पूर्व विधायक शीतल अंगूराल, जगबीर सिंह बराड़, पूर्व जिला अध्यक्ष रमन पब्बी, जिला महामंत्री राजेश कपूर, अशोक सरीन हिकी, अमरजीत सिंह गोल्डी,भाजपा स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश अध्यक्ष सनी शर्मा, पार्षद कुंवर सरताज, जिला उपाध्यक्ष मनीष विज, जिला सचिव अमित भाटिया, ऑफिस इंचार्ज योगेश मल्होत्रा, प्रमोद कश्यप, मुख्य रूप से उपस्थित थे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आर,पी,सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया था। सरदार आर,पी सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समय था जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आज भी हमें आपातकाल के काले दौर से सीखने की जरूरत है, ताकि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। सरदार आर,पी सिंह ने कहा कि आपातकाल के काले दौर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और हमें इसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा, ताकि वे हमारे लोकतंत्र की महत्ता को समझ सकें उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस का मानना है कि इस देश की सत्ता पर केवल और केवल उनके परिवार का हक है और वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं आपातकाल के दौरान प्रेस सहित देश के सभी नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और न्यायपालिका को उसकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया ष्ठद्धक्र और मीसा के तहत आपको जमानत की अपील करने का भी अधिकार नहीं था कोर्ट के सभी रास्ते बंद थे और सारा विपक्ष जेल में था 42 वां संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को भी बदल दिया गया था एक नेता एक परिवार देश से ऊपर हो गया था

राष्ट्रीय प्रवक्ता आर,पी सिंह ने बताया कि जब इस को कृत्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसे इसलिए भी याद रखना और याद दिलाना दोनों जरूरी है क्योंकि कांग्रेस जैसी तब थी वैसी ही आज भी है उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून पेश किया गया था जिसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा कांग्रेस की सरकारों ने 2013 तक वक्त अधिनियम में इतने बदलाव किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के असीमित अधिकार दे दिए गए जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी आरपी सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर सुपर पीएम को बिठाया गया था राहुल गांधी ने कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने फाड़ा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या चुनाव आयोग,क्या सुप्रीम कोर्ट,क्या कैग, क्या सीबीआई, क्या ई.डी, कांग्रेस ने हर संवैधानिक संस्था का न केवल अपमान किया बल्कि उन्हें देश और दुनिया में बदनाम भी किया आरपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को बार–बार बिना तथ्यों के निशाना बनाया गया उनके जीतने पर चुनाव आयोग सही हो जाता और हारने पर गलत हो जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं जनता ने उनके पैरों के नीचे से जमीन कब की खिसका दी है कांग्रेस और उसके सहयोगी परिवारवादी पार्टियों ने पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनका अपमान किया और इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की हिमाकत की थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 के निरस्तीकरण और सी.ए.ए के खिलाफ लोगों को गुमराह किया कर्नाटक और तेलंगाना में ओबीसी और दलितों का हक मार कर एक समुदाय विशेष को आरक्षण का लाभ दिया गया कर्नाटक तेलंगाना और हिमाचल को कांग्रेस ने आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है वह कभी संपत्ति का एक–रे की बात करते हैं तो कभी विरासत कर की बात करते हैं जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही जाती विरोधी की रही आज वह जाति की राजनीति कर देश में सामाजिक अराजकता फैलाना चाहती है और कांग्रेस ने ही बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में शुरू संविधान दिवस का भी विरोध किया वैसे भी बाबा साहब के खिलाफ इन्होंने क्या किया साजिश रची यह तो आप सब जानते ही हैं आर,पी सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के हर प्रश्न का मंतव्य देश सेना और सरकार की छवि को धूमिल करना होता है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक डोकलाम फेस ऑफ और ऑपरेशन सिंदूर तक राहुल गांधी और कांग्रेस ने केवल और केवल देश की जांबाज सेवा का अपमान किया चीन और पाकिस्तान के गुण गए और हर मंच पर भारत को बदनाम किया कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता कभी हिंदू टेरर तो कभी सैफरन टेरर की कहानी गढ़ते हैं तो कभी हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकियों से भी अधिक खतरनाक बताते हैं






# जालंधर भाजपा शहरी ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाया

## आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय–मनोरंजन कालिया

**रमन कुमार**

जलांधर–भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री अमरजीत सिंह गोल्डी और जिला उपाध्यक्ष मनीष विज की अध्यक्षता में 25 जून 1975 के आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यालय शीतला माता मंदिर में काला दिवस के रूप में मनाया गया।इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोरंजन कालिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रमन पब्बी,रवि महिन्द्रू और सुभाष सूद विशेष रूप से उपस्थित हुए।इस मौके पर मनोरंजन कालिया ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता बचाने के लिए लोगों की स्वतंत्रता को कुचला बल्कि लाखों निर्दोष नागरिकों को जेल में डाल दिया था।उन्होंने कहा कि आपातकाल कोई मजबूरी नहीं,बल्कि सत्ता की भूख और तानाशाही मानसिकता का परिणाम था। उन्होंने कहा कि 21 महीनों तक चले इस दमनकाल ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हिला कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल का विरोध केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि देश की आत्मा को बचाने का संघर्ष था।मनोरंजन कालिया ने कहा कि जब राष्ट्र की स्मृति कमजोर हो जाती है,तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है इसलिए युवाओं को 1975 की घटनाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का दावा करती है,जबकि इतिहास गवाह है कि उसी पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल की आग में झोंक दिया था।इस मौके पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष भूपिंदर कुमार,जिला सचिव मीनू शर्मा,जिला आईटी सेल अध्यक्ष दीपाली बागड़िया,किशन लाल शर्मा,अजमेर सिंह बादल,शमा आशीष सहगल, राजेश मल्होत्रा, मनीष बल, दिनेश खन्ना आदि उपस्थित थे।

# दुरुपयोग रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मेथनॉल की कूरियर के माध्यम से बिक्री पर रोक लगाई

## एस.डी.एम. को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में मिथाइल अल्कोहल की बिक्री पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया

**कैप्टन सुभाष चंदर**

जालंधर, खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में कूरियर सेवाओं के माध्यम से मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की बिक्री और डिलीवरी पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। इस जहरीले पदार्थ के अवैध व्यापार और संभावित दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए है। एक समीक्षा बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने सभी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में मेथनॉल की बिक्री और वितरण पर कड़ी नजर रखने और इसे विनियमित करने का निर्देश दिया। उन्होंने रसायन की अनधिकृत और बिना लाइसेंस वाली बिक्री, विशेषकर कूरियर सेवाओं की आड़ में होने वाली बिक्री को रोकने की महत्ता पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मेथनॉल का कारोबार करने वाले बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों की पहचान करने, इसे स्टॉक करने और बेचने की अनुमति वाले लाइसेंसधारियों की एक अलग सूची तैयार करने और लाइसेंस प्राप्त फर्मों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेथनॉल की खरीद, बिक्री और स्टॉक का विवरण देने वाली मासिक रिपोर्ट सख्त निगरानी के लिए एस.डी.एम. को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह कदम क्षेत्र में जहरीले पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को कंट्रोल करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

# ज़िला भाजपा द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि की अर्पित

## मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को किया साकार–सुशील शर्मा

**मनदीप कौर**



जालंधर, भारतीय जनता पार्टी ज़िला अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में जनसंघ के संस्थापक शहीद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय शीतला माता मंदिर में में पुष्पांजलि अर्पित की गई।इस दौरान सभी भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया गया।इस अवसर पर सुशील शर्मा ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा मुखर्जी ने देश को नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस सपने को साकार किया।उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए देश की अखंडता और एकता से बढ़कर कुछ नहीं था और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी।उन्होंने कहा कि राष्ट–कल्याण से लेकर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उनके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।इस मौके मनोरंजन कालिया ने डॉ. मुखर्जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारत माता के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान,दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे,यह कोई नारा नहीं बल्कि राष्ट की एकता के लिए दी गई उनकी तेजस्वी चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में जब सत्ता मौन थी, तब डॉ. मुखर्जी ने बलिदान की गूंज से राष्ट को एकसूत्र में बांधने का कार्य किया।इस अवसर पर राकेश राठौर ने कहा कि उनके विराट योगदान को देश कभी भुला नहीं पायेगा।उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्टवादी विचारक एवं सच्चे देश भक्त थे और एक देश मे दो कानून दो निशान के विरोध में उन्होंने प्राणों का बलिदान कर दिया था।उन्होंने कहा कि उनका बलिदान देश को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।इस अवसर पर केडी भंडारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद हमारे आदर्श हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर ही आज भाजपा की सरकार केंद्र में भी चल रही है।उन्होंने कहा कि वो हमारे विकास के स्तंभ थे और उन्होंने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं सदैव हम सबको राष्ट उत्थान व समाज सेवा हेतु प्रेरित करती रहेंगी।इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, पूर्व मंत्री व राष्टीय कार्यकारिणी सदस्य मनोरंजन कालिया,प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर,प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण देव भंडारी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, ि?ला महामंत्री एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की,राजेश कपूर और अमरजीत सिंह गोल्डी,जिला सचिव मीनू शर्मा और शाम शर्मा,जिला भाजपा ऑफिस को इंचार्ज योगेश मल्होत्रा,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमन पब्बी,सुभाष सूद,जिला भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष दीपाली बागड़ियां,शमा, अजमेर सिंह बादल, प्रमोद कश्यप,किशन लाल शर्मा,जिला उपाध्यक्ष अश्वनी भंडारी, मनोज

# जालंधर में एक सप्ताह में शुरू होगी 'ईजी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन'– मोहिंदर भगत

**एसके सक्सैना**



## कैबिनेट मंत्री ने इस परियोजना को पारदर्शिता और लोगों की सुविधा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया

जालंधर, पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने घोषणा की कि जालंधर में एक सप्ताह के भीतर 'ईजी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन'का काम शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आज सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रणदीप सिंह हीर के साथ उप रजिस्ट्रार दफ्तर परियोजना के चल रहे काम की समीक्षा की और राजस्व विभाग के अधिकारियों को लंबित काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि यह नई प्रणाली लोगों को कई दफ्तरो के चक्कर लगाने से बचाएगी साथ ही एजेंटों और बिचौलियों से छुटकारा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाएं प्रदान करने में यह सुधार संपत्ति रजिस्ट्रेशन को आसान, तेज और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के पंजीकरण तक की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे अनावश्यक देरी खत्म होगी और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य भर के सब–रजिस्ट्रार दफ्तरों में एयर कंडीशनिंग, वेटिंग हॉल, टोकन डिस्प्ले एलईडी आदि लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत डीड राइटर नाममात्र फीस पर उपलब्ध रहेंगे और बिना किसी परेशानी के पेशेवर तरीके से सहायता प्रदान करेंगे। श्री भगत ने कहा कि पंजाब सरकार नवीनतम तकनीकों के माध्यम से प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 'ईजी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन' परियोजना राजस्व विभाग की सेवाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।

# जलवायु क्षेत्र में भारत की ग्यारह वर्षों की प्रगति

**भूपेंद्र यादव**

मानव द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2011–20 के दशक में पृथ्वी का तापमान, पूर्व–औद्योगिक काल (1850–1900) की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। साथ ही, विकसित देश वैश्विक कार्बन बजट में असंगत हिस्सेदारी रखने के बावजूद जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने के प्रति इच्छुक नहीं दिखाई देते।

इस वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत के 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के प्राचीन वैदिक सिद्धांत ने सहस्राब्दियों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व की चुनौती से जूझ रही है, तो जलवायु प्रबंधन के प्रति भारत की कालातीत वैदिक ज्ञान की प्रतिध्वनि विश्व को मार्ग दिखा रही है।

एक ओर, वैश्विक समुदाय अक्सर जलवायु परिवर्तन से उपजी तापमान वृद्धि, अनियमित मौसम पैटर्न और आपदाओं में वृद्धि जैसी 'असुविधाजनक सच्चाइयों' में उलझा हुआ है। दूसरी ओर, भारत ने 'सुविधाजनक कार्रवाई' के दर्शन को सामने रखा है। हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित इस दृष्टिकोण ने पिछले ग्यारह वर्षों में भारत को एक कर्तव्यनिष्ठ वैश्विक जलवायु नागरिक में बदल दिया है।

अथर्ववेद का एक श्लोक है,

यत् किञ्च पृथिव्यां पृथिवीमनुत्तं हितं चेद् तत् तवायतु।

मा नः पृथिव्याः परं हिंसिष्ठाः।

पृथ्वी का जो कुछ भी हम खनन करते हैं, उसे जल्दी से भरने दें, हम पृथ्वी के प्राण–तत्वों पर आघात न करें और न ही उसके हृदय को क्षति पहुंचाएं।

यह श्लोक आधुनिक जलवायु विज्ञान से हज़ारों साल पहले के पुनर्निर्माण पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों को दर्शाता है। इस प्राचीन ज्ञान को जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर आधारित समकालीन नीतिगत ढाँचों में पिरोया गया है, जिससे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कार्रवाई का एक अनूठा तालमेल बना है।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, 2014 में पदभार ग्रहण करने के कुछ सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सरल लेकिन दूरगामी प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से अपनी जलवायु प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय में 'जलवायु परिवर्तन' को जोड़कर, उन्होंने जलवायु कार्रवाई को क्षेत्र–संबंधी चिंता के सीमित दायरे से निकालकर शासन की प्राथमिकता में ला दिया। 2015 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) का निर्माण इस प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है, जिसके द्वारा राज्यों को जलवायु संकट से निपटने से संबंधित संसाधन प्रदान किए जाते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित करके इस कदम का समर्थन किया, जिससे जलवायु कार्रवाई की एक संघीय व्यवस्था तैयार हुई।

2015 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने वैश्विक जलवायु वार्ता में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री खुद पेरिस गए और पेरिस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे धरती के संरक्षण में भारत की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। ऐसे देशों के विपरीत, जो जलवायु प्रतिबद्धताओं को बोझ के रूप में देखते हैं, भारत ने इसी वर्ष पेरिस में आयोजित कॉप–21 में अपने पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करके ठोस कार्रवाई का प्रदर्शन किया। यह देश की घरेलू अनिवार्यताओं और अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा निर्देशित वैश्विक समुदाय के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रकटीकरण था।

पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय यानी 2015 में ही एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का गठन हुआ, जो लगातार मजबूत होता गया और आज 120 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। इस गठबंधन ने सौर ऊर्जा संपन्न देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर सहयोग करने हेतु एक मंच तैयार किया है। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) को दिए गए प्रोत्साहन से, इसकी स्थापित क्षमता 2014 के मात्र 76 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 220 गीगावाट हो गई है और 2030 तक इसके 500 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत की बात करने तो हम आरई में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर हैं। एक दशक में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।



सरकार द्वारा अपनी कई योजनाओं के माध्यम से परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को गति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) से लाखों महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मिला, जो दर्शाता है कि जलवायु कार्रवाई का सामाजिक न्याय के साथ तालमेल कैसे बिठाना चाहिए। पीएम–कुसुम योजना (2019) ने किसानों को सौर ऊर्जा समाधानों के जरिये सशक्त बनाया, वहीं रूफटॉप सौर कार्यक्रम से पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी आयी है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की घोषणा की, जिसकी औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त, 2019 को हुई थी। इससे आपदा–रोधी अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में एक वैश्विक साझेदारी का निर्माण हुआ। स्वीडन के साथ साझेदारी में लीडआईटी (उद्योग में बदलाव के लिए नेतृत्व समूह) बनाया गया, जो जलवायु लक्ष्यों के लिए औद्योगिक बदलाव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सौर विनिर्माण (2020) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता मजबूत हुई, आयात पर निर्भरता कम हुई और एक मजबूत स्वदेशी सौर इकोसिस्टम का निर्माण हुआ।

2021 में ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 में भारत ने देश के जलवायु परिदृश्य को और मजबूत करते हुए ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने वक्तव्य में भारत के महत्वाकांक्षी अभियान पंचामृत की घोषणा की गई। पंचामृत यानी पाँच अमृत तत्व, जिसमें जलवायु प्रतिबद्धता को बढ़ाना और 2070 तक नेट–जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। इसी संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ़ – पर्यावरण के लिए जीवनशैली की शुरुआत की, ताकि वैश्विक स्तर पर नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ सामूहिक लड़ाई में शामिल किया जा सके। इस ऐतिहासिक प्रतिबद्धता ने भारत को विकासशील देशों के बीच जलवायु नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया।

2 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में कॉप 26 के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने आईआरआईएस (सुदृढ़ द्वीप देशों के लिए अवसंरचना) लॉन्च किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरीशस और यूके के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम से जलवायु–संवेदनशील देशों के प्रति वैश्विक एकजुटता प्रदर्शित की गई।

भारत ने 2022 में अपने एनडीसी को परिवर्तित करते हुए उसमें संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर स्वस्थ और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक गुणात्मक लक्ष्य के रूप में मिशन लाइफ को शामिल किया। इसी क्रम में, नवंबर 2022 में भारत ने अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी–एलईडी) प्रस्तुत की, जिसमें 2070 तक नेट–जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के साथ–साथ सतत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। इसी वर्ष राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ हुआ, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा, जो ऊर्जा स्वतंत्रता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की हमारी दृष्टि के अनुरूप है। वर्ष 2023 में विकसित भारत 2047 की घोषणा, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई, जो 2047 तक 卐पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था卐 तथा 卐प्रकृति और प्रगति卐 के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हुए विकसित राष्ट्र बनने के प्रति भारत का विज़न है। भारत की जलवायु कार्रवाई, 2047 तक विकसित भारत के विज़न के अनुरूप है। जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में कार्रवाई के अलावा, भारत ने व्यापक जलवायु रिपोर्टिंग का प्रदर्शन करते हुए द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट के साथ अपना अनुकूलन संवाद भी प्रस्तुत किया है।

2024 में बदलाव लाने वाली दो नागरिक केंद्रित पहलों की शुरुआत हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने सौर ऊर्जा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया, जबकि 卐एक पेड़ माँ के नाम卐 के शुभारंभ ने वनीकरण को एक जन आंदोलन का रूप दिया। इन कार्यक्रमों के जरिये प्रत्येक नागरिक को जलवायु कार्रवाई में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया गया।

ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए, 2025 में विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया। आम बजट 2025–26 में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बजट के साथ यह परमाणु ऊर्जा मिशन, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किये गये और संचालन योग्य एसएमआर विकसित करना है। निस्संदेह यह मिशन भारत को अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा। भारत 2030 तक अपने उन्नत एनडीसी को प्राप्त करने के लिए प्रगति–पाथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा पर है और 2030–35 की अवधि के लिए एनडीसी के संशोधन की तैयारी कर रहा है। भारत जलवायु कार्रवाई में निरंतर सुधार का प्रदर्शन कर रहा है और संभावना है कि देश शीघ्र ही पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना भी प्रस्तुत करेगा।

भारत, शमन उपायों के माध्यम से आपूर्ति पक्ष पर और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण–अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देकर मांग पक्ष पर जलवायु कार्रवाई कर रहा है।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत ने जनभागीदारी के आह्वान के साथ जलवायु कार्रवाई को सरकारी जिम्मेदारी से एक जन आंदोलन में बदल दिया है।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल वसुधैव कुटुम्बकम के प्राचीन भारतीय सिद्धांत को मूर्त रूप देती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, लीडआईटी और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (आईबीसीए) चुनौतियों पर अटके रहने के बजाय, सिद्धांतों पर अमल करने और समाधान साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान, पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह से अलग कई अन्य कार्य समूहों में जलवायु संबंधी विचारों को मुख्यधारा में लाया गया। विकास कार्य समूह ने सतत विकास के लिए जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि ऊर्जा कार्य समूह ने न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। यह पहले दिखाती हैं कि जलवायु संबंधी चिंताएँ क्षेत्रीय सीमाओं को कैसे पार करतीं हैं। भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की, जिससे स्थायी जैव ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच तैयार हुआ।

असुविधाजनक सत्य को सुविधाजनक कार्रवाई में बदलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि जलवायु नेतृत्व के लिए न केवल वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता होती है, बल्कि मानवीय कार्रवाई को प्राकृतिक सामंजस्य के साथ जोड़ने की समझ की भी जरूरत होती है।

***(भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं)***

# भारतीय कामगारों का सशक्तिकरण –रोजगार में बढ़ोतरी और श्रमिक कल्याण के डिजिटल उपाय

**वी. अनंत नागेश्वरन, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार**

आधुनिक डिजिटल युग में, चैटबॉट, पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था और प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा संचालित ई–गवर्नेंस पोर्टल ने सरकार को लोगों के बेहद करीब ला दिया है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार रोजगार वृद्धि और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने को फिर से परिभाषित और पुनर्संयोजित कर रही है। अब प्रक्रियाएं अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक–केंद्रित बन रही हैं। योजना से संबंधित पोर्टल अब 卐ऑल–इन–वन卐 (एकल सुविधा) प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी, मैन्युअल प्रक्रियाओं और प्रशासनिक बोझ कम करते हुए कार्यक्रमों के बारे में निर्बाध ज्ञान प्रवाह और लाभ मापन की सुविधा प्रदान करते हैं। योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़े जाने और विभिन्न योजनाओं के साथ इसके अंतर्संबंध से किसी को दो बार लाभ लेने से रोकने के साथ ही यह सुनिश्चित होता है कि लाभ समय पर लक्षित लोगों तक ही पहुंचें। आपस में जुड़े पोर्टल कामगारों को लाभकारी योजनाओं तक पहुंचने और आवेदन की स्थिति जानने, रोज़गार के अवसरों का पता लगाने और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। जबकि ये नियोक्ताओं को राष्ट्रीय प्रतिभा पूल के उपयोग में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कौशल और अनुभव के आधार पर कामगारों की भर्ती संभव हो पाती है। इसके अतिरिक्त, ये पोर्टल असंगठित श्रमिकों, नौकरी के इच्छुक कामगारों, नियोक्ताओं और रोज़गार के अवसरों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में योगदान देते हैं, जिससे नीति निर्माताओं को सूचित, डेटा–समर्थित निर्णय लेने की सहूलियत मिलती है। किसी बड़े संकट के समय, महामारी इत्यादि के दौरान, ये डेटाबेस बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे, जिससे ज़रूरतमंदों की शीघ्रता से पहचान और समय पर सहायता सुनिश्चित हो सकेगी। यह डिजिटल शासन में परिवर्तन को सुव्यवस्थित कर रहा है, नागरिकों को सशक्त बना रहा है और कल्याणकारी प्रयासों की व्यापकता और प्रभावशीलता बढ़ा रहा है। इन पहल के कुछ उदाहरणों की यहां चर्चा की गई है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल इस परिवर्तनकारी पहल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2015 में आरंभ किए गए इस पोर्टल ने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 करोड़ 50 लाख से अधिक कामगारों के पंजीकरण के साथ, यह एक 卐वन–स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म卐 के रूप में काम कर रहा है जो नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को देश भर में रोज़गार के अवसरों से जोड़ता है। इस पर उन्हें करियर काउंसलिंग, जॉब मैचिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षुता), कौशल विकास पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। किसी राज्य विश्वविद्यालय से तुरंत स्नातक होने वाला छात्र पहले मोबाइल फ़ोन के ज़रिए देश भर में नौकरी के अवसरों को जानने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर आज, एनसीएस की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से स्थान के हिसाब से पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकरण के ज़रिए, देश भर में नौकरियों की खोज कर सकता है, करियर और नौकरी संबंधी परामर्श प्राप्त कर सकता है और यहां तक कि स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पोर्टल के ज़रिए आवश्यक कौशल भी हासिल कर सकता है। यह सब उसे फ़ोन पर या स्थानीय रोजगार मेलों में शामिल होकर मिल सकता है। एनसीएस परियोजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57 हजार रोज़गार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल को स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), उद्यम, ई–श्रम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), पीएम गतिशक्ति, डिजीलॉकर और अन्य के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हितधारकों की उन तक पहुंच और दक्षता में वृद्धि हुई है। यह पोर्टल लगभग 30 राज्यों और निजी रोजगार पोर्टलों से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कामगारों को नौकरी के



अवसरों तक व्यापक पहुंच हो रही है। इसी तरह, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन और व्यापार सुगमता को बढ़ाते हैं तथा विवादों का तेजी से समाधान और दावे तथा श्रमिकों की शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करते हैं। ईएसआईसी धनवंतरी मॉड्यूल अस्पतालों और औषधालयों को मरीजों का रिकॉर्ड (परीक्षण इत्यादि) पिछले मामले के इतिहास आदि की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे रोगी की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होती है। ये पहल सरकार के संकल्प के स्पष्ट प्रमाण हैं कि प्रौद्योगिकी के लाभ से विभिन्न पहल द्वारा सभी के लिए अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी सेवा मुहैया कराने के कल्याणकारी उपायों में कोई भी पीछे न छूटे। रोजगार का दूसरा पहलू सामाजिक सुरक्षा है। भारत में एक बड़ा अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है। ऐसे रोजगार में नियोक्ता द्वारा कोई लिखित अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। इन कामगारों के लिए, बीमारी, चोट, दुर्घटना, नौकरी छूटना या अन्य आपात स्थिति जैसी कोई भी घटना तुरंत विपत्ति में बदल सकती है। अब सरकार के सामाजिक सुरक्षा के उपाय अस्थायी संकट को आजीवन कठिनाई में बदलने से रोकते हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों से इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हाल तक लाखों असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों तक जागरूकता और पहुंच सीमित थी। पर ई–श्रम पोर्टल ने इस चुनौती का समाधान किया है। असंगठित श्रमिकों को अब सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट पहचान मिला है। वर्ष 2021 में आरंभ किए गए इस पोर्टल पर 30 करोड़ 70 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। यह पोर्टल लगभग 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत कर श्रमिकों के लिए 卐एकल समाधान卐 के रूप में कार्य करता है, जिससे लाभों को लक्षित रुप से पहुंचाना, उन तक बेहतर पहुंच और योजना संतृप्ति (योजना लाभ) संभव हो पाता है। केंद्रीय बजट 2025–26 में गिग श्रमिकों (अल्पकालिक, अनुबंध–आधारित नौकरी करने वाले) का ई–श्रम से पंजीकरण कर विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया गया है और उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ श्रमिकों का विवरण साझा करके, पोर्टल राज्य स्तर पर श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की बेहतर योजना और कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा, स्किल इंडिया डिजिटल हब, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम–एसवाईएम), सरकारी योजनाएं खोजने के लिए 卐वन स्टॉप卐 समाधान प्रदान करने वाला राष्ट्रीय प्लैटफ़ॉर्म माईस्कीम, दिशा योजना आदि के साथ एकीकृत किया गया है। यह श्रमिकों को ई–श्रम पर एक बार पंजीकरण कराने से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कई योजना पोर्टलों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। इससे योजना की पात्रता, योजना के लाभों, नौकरी के अवसरों का पता लगाने, कौशल प्रशिक्षण, पेंशन और बीमा जैसे लाभ की जानकारी एक ही स्थान पर मिलती है। इसकी पहुंच और भी व्यापक बनाने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिणी परियोजना की 22 भाषाओं वाली एक बहुभाषी सुविधा को ई–श्रम में जोड़ा गया है। परिचालन को सरल बनाने के लिए राज्य माइक्रोसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इन प्रयासों से उल्लेखनीय सफलता और घरेलू स्तर पर सराहना के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नवीनतम डेटाबेस अद्यतन के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64 दशमलव 3 प्रतिशत हो गया है। आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थियों के मामले में भारत 94 करोड़ 13 लाख के साथ दूसरे स्थान पर है। यह बढोतरी देश में सामाजिक सुरक्षा दायरे की गणना में 32 केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के सरकार के प्रयासों का परिणाम है। विश्व सामाजिक सुरक्षा 2026 के लिए डेटा पूलिंग की चल रही कवायद के तहत सामाजिक सुरक्षा दायरे में इस विकास को शामिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसी क्रम में, 34 करोड़ 60 लाख से अधिक सदस्यों वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ के द्वितीय चरण में बदलाव के लिए कई डिजिटल सुधार लागू किए हैं। इनसे सदस्यों की पहुंच बढ़ी है और नियोक्ताओं का काम आसान हो गया है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू करने, एकीकृत केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने, ई–पासबुक, उमंग ऐप, योगदानकर्ताओं के अंशदान का ई–संग्रह और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के प्रावधान सहित प्रमुख पहल से सदस्यों की सुविधा बढ़ी है। ईपीएफओ ??के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली आरंभ होने से देश में कहीं से भी पेंशन प्राप्त करने से 77 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, ऑटो–क्लेम सेटलमेंट सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपए करने से लगभग 7 करोड़ 50 लाख सदस्यों को सुगमता होगी और दावों का निपटान तेजी से हो सकेगा। ईपीएफओ ??ने फंड ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाया है, जिससे एक करोड़ 25 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ हुआ है और लगभग 90 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक अंतरण सुगम हुआ है। इन सुधारों और ईपीएफओ के आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण दक्षता बढ़ाने और मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने से सदस्यों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रणाली संचालन आसान हो जाएगा।

सरकारी के नीतिगत हस्तक्षेपों को उद्योग की सक्रिय भागीदारी का समर्थन आवश्यक है। उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका का एक प्रमुख उदाहरण ई–श्रम पहल है, जहां गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों (संस्थागत श्रमिकों) के लिए सामाजिक सुरक्षा का सफल कार्यान्वयन काफी हद तक प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स की भागीदारी पर निर्भर करता है। नियोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि एक सुरक्षित, संरक्षित और संतोषजनक कार्यस्थल बनाना, साथ ही श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए, वंचित और कमजोर समूहों को लक्षित और निरंतर समर्थन प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। यह समर्थन आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देगा और कार्यबल तथा अर्थव्यवस्था में भागीदारी की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।

# पंजाब सरकार ने विशेष बुजुर्ग कल्याण अभियान के तहत अयोग्य पेंशन खातों से 166 करोड़ रुपये की वसूली की-डॉ. बलजीत कौर

## साडे बुजुर्ग साडा मान सर्वेक्षण के माध्यम से 166 करोड़ रुपये की वसूली हुई, शेष 86 करोड़ रुपये की जल्द वसूली की जाएगी- सामाजिक सुरक्षा मंत्री

पंकज

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई और उनके मान–सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में, मृतक पेंशनधारकों की पहचान करने और सही लाभार्थियों को पेंशन का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साडे बुजुर्ग साडा मान शीर्षक के अंतर्गत एक विशेष सर्वेक्षण चलाया गया। आज इस बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से 67,852 मृतक पेंशनधारकों की पहचान की गई, जिनके खातों में समय के साथ लगभग 252 करोड़ रुपये एकत्र हो चुके थे। इनमें से जिला सामाजिक सुरक्षा

अधिकारियों और बैंकों के सहयोग से अब तक 166 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष 86 करोड़ रुपये की वसूली में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह प्राप्त राशि योग्य लाभार्थियों को पेंशन लाभ के रूप में दी जाए। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में लगभग 35 लाख बुजुर्ग, विधवाएं, अनाथ बच्चे और दिव्यांग व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने बैंक खातों में 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़रों की सराहना की, जो घर–घर जाकर पेंशनधारकों की स्थिति और भलाई के संबंध में सही जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत हर योग्य लाभार्थी को पेंशन उपलब्ध करवा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में मई 2025 तक 43,644 नए योग्य लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योग्य लाभार्थियों को पेंशन बिना किसी देरी के पारदर्शी ढंग से प्रदान की जाए। पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए डॉ. कौर ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान %एम–सेवा% ऐप का प्रभावी उपयोग किया गया, ताकि रियल–टाइम डेटा संग्रहण और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब के लोगों को सरकारी लाभों का सही और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के कल्याणकारी अभियान और सत्यापन सर्वेक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे। जिला अधिकारियों, बैंकों और सामाजिक सुरक्षा विभाग के बीच सक्रिय तालमेल की सराहना करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को बकाया राशियों की वसूली की गति बनाए रखने और समाज के बुजुर्गों व वंचित वर्गों की भलाई के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखने के निर्देश दिए।

# डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने संभावित बाढ़ के मद्देनजर किया ब्यास दरिया किनारे बसे गांवों का दौरा

## कहा, सरकार की तरफ से 1.20 करोड़ रुपए की लागत से बनवाए गए स्टड

एसके सक्सैना

होशियारपुर/मुकेरियां,–मानसून सीज़न की शुरुआत से पहले संभावित बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज एसडीएम मुकेरियां कमलजीत सिंह और ड्रेनेज विभाग के एसडीओ सुखप्रीत सिंह के साथ ब्यास दरिया के किनारे बसे गांवों नौशहरा पत्तन, होशियारपुर कलोता और महिताबपुर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरह सतर्क और चिंतित है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पूर्व में आई बाढ़ों के कारण हुए भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही 1.20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी थी, जिससे ब्यास दरिया के किनारों पर सुरक्षा के लिए स्टड (रक्षक बांध) बनाए गए हैं और संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्रामीणों की मांग पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जल्द जारी की जाएगी ताकि बाकी बचे इलाकों में भी स्टड निर्माण संभव हो सके और गांवों तथा कृषि भूमि को बाढ़ के पानी से बचाया जा सके। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की इस तत्परता की सराहना करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। किसानों ने विशेष रूप से सरकार द्वारा निर्बाध बिजली आपूर्ति और खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के प्रयासों को सराहा। इस मौके पर सरपंच जसविंदर सिंह, नंबरदार बलजीत सिंह, बाबा मलकीत सिंह, नंबरदार अवतार सिंह, रविंदर सिंह रम्मी, कुलजीत सिंह, तरसेम सिंह, किसान नेता और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

# राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूटी चंडीगढ़ में आधारशिला रखी गई और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया

मनदीप कौर

चंडीगढ़, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री, श्री बंदी संजय कुमार ने आज केंद्र शासित प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 50 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा किया। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए, यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा ने बिजली वितरण के निजीकरण, रूफटॉप सोलर संतृप्ति और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में चंडीगढ़ के मजबूत प्रदर्शन सहित कई क्षेत्रों में शहर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज उद्घाटन और शिलान्यास की गई पांच प्रमुख परियोजनाएं शहर भर में शिक्षा, आवास, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में व्यापक परिवर्तन का प्रतीक हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कॉमर्स कॉलेज, सेक्टर 50 में हॉस्टल ब्लॉक (लड़के और लड़कियां) का उद्घाटन किया। उन्होंने वाटर वर्क्स, सेक्टर 39 में 2,500 किलोवाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट; गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कजहेड़ी के एक्सटेंशन ब्लॉक; और पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 46 में आईटी ब्लॉक का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धनास में चंडीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में 144 आवासीय इकाइयों के निर्माण की आधारशिला रखी।

## श्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि चंडीगढ़– एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सच्चा प्रतीक है, भारत के नए कानूनी कोड को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला राज्य चंडीगढ़ है

अपने संबोधन में, श्री बंदी संजय कुमार ने चंडीगढ़ को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का सच्चा अवतार बताया। उन्होंने विकास, पारदर्शिता और सुरक्षा में शहर की प्रगति की सराहना की और कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सड़क और सार्वजनिक परिवहन आधुनिकीकरण, डिजिटल शासन, जीवन–यापन में आसानी की पहल और ग्रीन इंडिया तथा स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से नागरिकों के जीवन में ठोस सुधार आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चंडीगढ़ देश में तीन नए कानूनी ढाँचों– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर है। उन्होंने कहा, ‘आज उद्घाटन और शिलान्यास की गई परियोजनाएँ न केवल चंडीगढ़ के विकास को दर्शाती हैं, बल्कि %सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास% के सिद्धांत के तहत व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन पहलों से शैक्षिक गुणवत्ता, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, नए आईटी ब्लॉक के माध्यम से युवाओं को प्रौद्योगिकी कौशल से सशक्त बनाया जाएगा और धनास में आवास परियोजना के माध्यम से पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नशीली दवाओं के उन्मूलन, साइबर अपराध की रोकथाम, महिला सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को संबोधित करने में चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने शांति, आपदा प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में केंद्र शासित प्रदेश का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विकसित भारत 2047 के विजन को देखते हुए, श्री बंदी संजय कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। इस मिशन के हिस्से के रूप में, चंडीगढ़ को नॉलेज हब, वेलनेस सिटी और स्मार्ट गवर्नेंस के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस परिवर्तन के प्रति समर्पण और पहल के लिए यूटी चंडीगढ़ के सभी अधिकारियों, योजनाकारों, इंजीनियरों, श्रमिकों और नागरिकों को बधाई दी। इस अवसर पर चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती हरप्रीत कौर बबला; भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री सत्य पाल जैन; चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक श्री पुष्पेन्द्र सिंह, वित्त सचिव श्री दीप्रवा लाकड़ा, नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण सचिव श्री सौरभ कुमार, मुख्य अभियंता श्री सी.बी. ओझा तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री द्वारा पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की घोषणा

## कहा, राज्य सरकार कानून बनाने से पहले सभी पक्षकारों से करेगी सलाह–मशविरा

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों और सर्वधर्म बेअदबी रोकथाम कानून मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंजाब, महापुरुषों, संतों और पैगंबरों की पावन धरती है, जिन्होंने पूरी दुनिया

को आपसी प्रेम और सहनशीलता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि पंजाब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को उदाहरणीय सजा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ठोस राज्य स्तरीय कानून को बनाने के लिए सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेगी ताकि अपराधियों को सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने मौजूदा कानूनी खामियों पर चिंता व्यक्त की, जो इस प्रकार के अक्षम्य अपराधों के दोषियों को खुलेआम घूमने की अनुमति देती हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य बताया। हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन बेअदबी की घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को उदाहरणीय सजा दी जाएगी।

# पंजाब सरकार का संकल्प - शहरी निवासियों को विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं प्रदान करना-डॉ. रवजोत सिंह

## कहा, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा, स्थानीय निकाय मंत्री ने मोहाली की शहरी स्थानीय इकाइयों के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक

कैप्टन सुभाष चंदर

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरी निवासियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी दिशा में पंजाब के शहरों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह विचार आज पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने यहां वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के अधिकारियों तथा कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने पंजाब के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) की शहरी स्थानीय इकाइयों – नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, राजपुरा, बनूड, ज़ीरकपुर, लालडू, नवा गांव, घडूआं और कुराली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को शहरी विकास के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि मोहाली की शहरी स्थानीय इकाइयों में लैंडस्केपिंग, सड़कों का विकास, मोहाली शहर के अधीन आने वाले गांवों का सौंदर्यीकरण, शहरी नागरिकों की सुविधा संबंधी कार्य, और शहरों में बनाई जा रही इमारतों का निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। डॉ. रवजोत सिंह ने प्रगति अधीन विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहा कि ये विकास कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी नागरिक सुविधाएं पंजाब सरकार की प्राथमिकता हैं और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तेजवीर सिंह, सी.ई.ओ. पीएमआईडीसी श्रीमती दीप्ति उप्पल, संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय श्री जगदीप सहगल, नगर निगम मोहाली के आयुक्त श्री परमिंदर पाल सिंह, ए.डी.सी. शहरी विकास स अनमोल सिंह धालीवाल, चीफ इंजीनियर श्री नरेश बत्ता तथा नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, राजपुरा, बनूर, ज़ीरकपुर, लालडू, नवा गांव, घडूआं और कुराली के कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।

# जगदीश शर्मा आम आदमी पार्टी के हल्का मोगा संगठन प्रभारी मनोनीत

## ब्राह्मण समाज एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर– दीप दारापुरिया

मोगा [ कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा] ब्राह्मण सभा मोगा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुप्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता,जगदीश शर्मा जी जन कल्याणार्थ कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। धार्मिक, समाजिक संगठनों के साथ जुड़ कर समर्थानुसार जरूरतमंद परिवारों को निस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान कर रहे हैं।करोना महांमारी के दौरान देशव्यापी लॉक्डाऊन में अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंद परिवारों की सहायता करते रहे। प्रशासन,धार्मिक एवं समाजिक संगठनों से की अक्सर सम्मानित हो रहे हैं। शर्मा जी बहुत ही कर्मठ

एवं निष्ठावान हैं संगठन में जो भी कार्य उन्हें दिया जाता बहुत ही परिश्रम से निभा रहे है। उनकी मेहनत एवं लगन को मध्य नजर रखते हुए ही पार्टी की ओर से उन्हें पहले ही विशेष जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं। वह जिलाध्यक्ष मोगा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ एवं जिला मोगा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सदस्य की जिम्मेदारी निष्ठा से निभा रहे हैं। शर्मा जी की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए पार्टी संगठनात्मक ढांचे में विशेष जिम्मेदारी जिला मोगा संगठन प्रभारी मनोनीत किया गया है। दीप दारापुरिया ब्राह्मण के विशेष प्रतिनिधि एवं पूर्व सदस्य खादी बोर्ड पंजाब सरकार ने प्रैस वार्तालाप दौरान बताया कि जगदीश शर्मा की उक्त नियुक्ति से ब्राह्मण समाज एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर हैं। उनकी इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं मे एक नई उर्जा एवं उमंग का संचार होगा। उन्होंने शर्मा को नव पद प्रतिष्ठा हेतु हार्दिक बधाई देते हुए पंजाब प्रदेश हाईकमान का आभार व्यक्त किया। शर्मा ने उक्त नियुक्ति हेतु हाईकमान का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सौंपी हुई जिम्मेदारी मेहनत एवं लगन से निभाने हेतु आश्वासन दिया।

# केजरीवाल की दोहरी नीति ने पंजाब को बनाया पुलिस राज; आपातकाल की काली यादें फिर जीवित- चुग

## पंजाब में संविधान नहीं, केजरीवाल की तानाशाही चल रही है– चुग

मनदीप कौर

चंडीगढ़, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को आप सरकार की ‘राजनीतिक प्रतिहिंसा’ बताते हुए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। चुग ने कहा कि ‘अगर मजीठिया वाकई दोषी थे, तो केजरीवाल ने 2018 में उनसे माफ़ी क्यों मांगी? और यदि वह माफ़ी सही थी, तो यह गिरफ्तारी कैसे जायज़ है? दोनों बातें एक साथ सच्ची नहीं हो सकतीं–यही

केजरीवाल का असली चेहरा और ढोंग है। उन्होंने कहा कि पंजाब तेजी से पुलिस राज की ओर बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल के पचास वर्ष पूरे होने पर केजरीवाल ने उसी तानाशाही सोच को पंजाब में पुनर्जीवित कर दिया है, जहाँ सरकार के आदेश पर विरोधी आवाज़ों का गला घोंटा जाता था। चुग ने कहा कि युद्ध नशियान विरुद्ध अभियान महज़ एक पीआर स्टंट साबित हुआ है, जिसका असली मक़सद नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को डराकर चुप कराना था। यदि मजीठिया के खिलाफ कोई साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और न्याय अवश्य मिले – लेकिन सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर राज्य तंत्र का दुरुपयोग न करे।चुग ने पंजाब के तमाम विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वे इस दमनकारी मानसिकता और तानाशाही शासन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएँ। साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता से अपील की कि वे इस संविधान–विरोधी, अलोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक तरीक़े से उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा, ‘जिस पंजाब ने इंदिरा गांधी के आपातकाल को चुनौती दी थी, आज उसी जुझारूपन की फिर से आवश्यकता है।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688



# प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंजाब वित्त विभाग राज्य सरकार के कुछ विभागों के विलय की प्रक्रिया में सक्रिय-हरपाल सिंह चीमा

## वित्त विभाग के तहत विभिन्न निदेशालयों के विलय के पंजाब मंत्रिमंडल के फैसले का वित्त मंत्री ने किया स्वागत

पंकज

चंडीगढ़, –पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज बताया कि वित्त विभाग राज्य सरकार के कुछ छोटे और परस्पर जुड़े विभागों के विलय की एक रणनीतिक पहल पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना है। पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों के विलय के निर्णय का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस कदम से प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और राज्य के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत संभव हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस रणनीतिक पुनर्गठन से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 2.64 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन विभागों के एकीकरण से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा,

बल्कि इन महत्वपूर्ण विभागों की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। यह पुनर्गठन एक अधिक चुस्त और वित्तीय रूप से जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम है। आगे जानकारी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि वित्त विभाग अन्य राज्य सरकार के विभागों के पुनर्गठन और विलय की दिशा में भी व्यापक प्रयास कर रहा है, ताकि शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक सरल बनाया जा सके, दोहराव को समाप्त किया जा सके और एक अधिक संगठित व उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा, आपस में मिलती–जुलती कार्यप्रणाली या समान उद्देश्यों वाले विभागों को एक साथ लाकर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार निर्णय लेने और क्रियान्वयन की गति में उल्लेखनीय वृद्धि की आशा कर रही है, जिससे अंततः पंजाब के नागरिकों को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी जनसेवाएं मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के अंतर्गत कई निदेशालयों के विलय को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और खर्चों को कम करना है। जिन निदेशालयों का विलय किया जा रहा है, उनमें निदेशालय लघु बचत, बैंकिंग और लॉटरी; निदेशालय वित्तीय संसाधन एवं आर्थिक खुफिया (डी एफ आर ई आई ) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीईडी ); तथा निदेशालय कोषागार एवं लेखा, पेंशन और एनपीएस शामिल हैं। इस एकीकरण से कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार और शासन व्यवस्था में मजबूती आने की उम्मीद है।

# पंजाब विधानसभा स्पीकर ने श्री गुरु तेग बहादर जी की 350वीं शताब्दी मनाने संबंधी सुझाव लेने के लिए भाई बलदीप सिंह जी और बीबी नवप्रीत कौर से की बैठक

एसके सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने श्री गुरु तेग बहादर जी की 350वीं शताब्दी मनाने के संबंध में सुझाव लेने हेतु सैन फ्रांसिस्को से आईं बीबी नवप्रीत कौर और भाई बलदीप सिंह जी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बीबी नवप्रीत कौर ने %गावनी% शीर्षक से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए विभिन्न देशों की 31 महिला रागियों द्वारा 31 रागों का गायन किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, विविधता और मानव गरिमा के लिए गुरु साहिब की बेमिसाल कुर्बानी विश्व नागरिकों को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। इस मुलाकात के दौरान बीबी नवप्रीत कौर ने बताया कि ये 31 महिला रागियां भारत के 9 विभिन्न शहरों और पंजाब के 7 अलग–अलग शहरों में गुरु कीर्तन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से लोग गुरबाणी के उन शब्दों से जुड़ेंगे जो शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं और इस शताब्दी वर्ष में गुरु साहिब की विरासत का प्रचार–प्रसार करेंगे। बैठक में मिस सोफिया कौर भी उपस्थित थीं।

# मुख्य मंत्री ने नीति आयोग की उच्च स्तरीय टीम के समक्ष राज्य की मांगें जोरदार ढंग से उठाईं

## पानी और कृषि को बचाकर राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए मांगी मदद

मनदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नीति आयोग की टीम के सामने राज्य का पक्ष जोरदार ढंग से रखा और समर्थन की मांग की ताकि एक ओर पंजाब का समग्र विकास सुनिश्चित हो और दूसरी ओर इसके हितों की भी रक्षा हो। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद और प्रोग्राम डायरेक्टर संजीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ विचार–विमर्श के दौरान मुख्य मंत्री ने कहा कि यह उपयुक्त समय है जब आयोग को पानी और कृषि से संबंधित पंजाब की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए खुले दिल से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और छह जिले अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का सीमा पर स्थित हैं। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर को विशेष रियायतें देने से पंजाब के सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

# मिड-डे मील स्टाफ को मिलेगा 16 लाख रुपये का बीमा कवर-हरजोत बैंस

## स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,000 से अधिक कुक–कम–हेल्परों के लिए किया समझौता– शिक्षा मंत्री

पंकज

चंडीगढ़, एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने केनरा बैंक के साथ साझेदारी में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,301 मिड–डे मील कुक–कम–हेल्परों को 16 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू की है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस और स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस की उपस्थिति में आज यहां डायरेक्टोरेट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (मिड–डे मील) और केनरा बैंक, चंडीगढ़ के बीच एक समझौता (एमओयू) साइन किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य

कुक–कम–हेल्परों को वित्तीय सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह कवर व्यापक लाभ प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 16 लाख रुपये का बीमा कवर और हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर 18 लाख रुपये का बीमा कवर शामिल है। इसके अलावा यह योजना बिना जीरो बैलेंस की शर्त के सरल बैंकिंग, खाता धारकों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपये तक की तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा या पिछले महीने के कुल वेतन का 50 प्रतिशत तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करती है। स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह योजना इन कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी, ताकि वे राज्य की शिक्षा प्रणाली के समर्थन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। यह पहल सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक–कम–हेल्परों के लिए वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

# बलजीत सिंह खालसा को दीनानगर संगठन का प्रभारी नियुक्त किया गया

सोनू, रविंदर

गुरदासपुर, 26 जून (सोनू बलजीत सिंह खालसा हलका दीनानगर संगठन इंचार्ज व जिला सचिव व चेयरमैन मार्केट कमेटी मंडी बोर्ड दीनानगर व सरपंच पुरानासला को पार्टी द्वारा संगठन इंचार्ज नियुक्त किए जाने पर बधाई दी गई तथा हलका दीनानगर पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक तक गांव बूथ कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे तथा आने वाले दिनों में हलका दीनानगर संगठन को पंजाब का सबसे मजबूत संगठन बनाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव तक हम गांव–गांव तक पहुंचेंगे और पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं,

कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर पार्टी की विचारधारा और भगवंत सिंह मान की जनहितैषी नीतियों को घर–घर तक पहुंचाएंगे।

# भगवंत मान सरकार और अनन्या बिरला फाउंडेशन ने नशे के खिलाफ जंग में तेजी लाने के लिए मिलाया हाथ

## डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए समझौता

कैप्टन सुभाष चंदर

चंडीगढ़, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता पंजाब सरकार और डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली, तथा विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अमृतसर के बीच अनन्या बिरला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने की यह अनूठी पहल राज्य में नशे के खतरे से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम और पुनर्वास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ युद्ध ने राज्य में नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस आपूर्ति के खत्म होने के साथ नशे से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मुख्य मंत्री ने कहा कि नशा पीड़ितों को नशे के जाल से बाहर निकालने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करने के लिए सरकार न केवल विभिन्न सुविधाओं से लैस पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रही है, बल्कि नशे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा विरोधी अभियान के दूसरे चरण में डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करके मनो–सामाजिक देखभाल का एक व्यापक मॉडल लागू किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह इकाई मेडिकल

अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों और फंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाकर नशा विरोधी अभियान में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि यह इकाई पुनर्वास से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने, ओ.ओ.ए.टी. (आउटपेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट) क्लीनिकों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और आम लोगों तक आसान पहुंच के प्रयासों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह इकाई पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह केंद्रीकृत इंटेलिजेंस इकाई नशा छुड़ाने, पुनर्वास और ओ.ओ.ए.टी. मरीजों के बारे में ठोस डेटा प्रदान करेगी, प्रभावी नीतियां डिजाइन करने और लागू करने में मदद करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एम्स के राष्ट्रीय ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर, आई.आई.टी. रोपड़, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई और पी.जी.आई. चंडीगढ़ जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ इस इकाई को समय–समय पर सहायता प्रदान करेंगे। मुख्य मंत्री ने कहा कि यह इकाई एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पंजाब पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और डेटा साइंस से संबंधित संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि अनन्या बिरला फाउंडेशन (ए.बी.एफ.) इस इकाई की तकनीकी क्षमताओं और संसाधनों के संबंध में सहायता प्रदान करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम एक केंद्रीकृत तकनीकी इकाई के रूप में एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें पटियाला, जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली के पांच मेडिकल कॉलेज क्लस्टर संसाधन केंद्रों के रूप में काम करेंगे।

# गुणवत्ता कंट्रोल मुहिम : गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा खराब कारगुज़ारी वाले जिलों के ख़िलाफ़ कार्यवाही के हुक्म

## मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार कृषि वस्तुओं के गुणवत्ता कंट्रोल के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी : कृषि मंत्री

पंकज

चंडीगढ़, खराब कारगुज़ारी वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों पर शिकंजा कसते हुये पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गुणवत्ता कंट्रोल मुहिम में पीछे चल रहे जिलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत जवाबदेही तय करने और अधिक सुधार को यकीनी बनाने के लिए सासाहिक समीक्षा भी की जायेगी। स. खुड्डियां ने कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डा. बसंत गर्ग के साथ आज यहाँ विभाग के चल रहे प्रोजेक्टों, स्कीमों और खरीफ सीजन के कामों का जायज़ा लिया। गुणवत्ता कंट्रोल मुहिम के नतीजों की समीक्षा करते हुये कृषि मंत्री ने लक्ष्यों से पिछड़ने और बुरे प्रदर्शन वाले जिलों का सख़्त नोटिस लिया। उन्होंने कृषि डायरैक्टर को डिफालटर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने और कृषि सामग्री की सैंपलिंग प्रक्रिया की सासाहिक समीक्षा को यकीनी बनाने के हुक्म दिए। स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गुणवत्ता कंट्रोल सम्बन्धी किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।गुणवत्ता कंट्रोल को बनाये रखने के लिए डा. बसंत गर्ग ने कृषि डायरैक्टर को हिदायत की कि वह सभी जिलों को दिए गए लक्ष्यों के अनुसार कृषि उत्पादों की बाकायदा सैंपलिंग को यकीनी बनाएं। उन्होंने कृषि डायरैक्टर को समय पर दखल और सुधारात्मक कार्यवाहियों के द्वारा गुणवत्ता मापदण्डों को बनाये रखने के लिए निरंतर निगरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। विभाग के डायरैक्टर स. जसवंत सिंह ने कृषि मंत्री को बताया कि कीटनाशकों के 826 नमूनों में से 16 गलत ब्रांडिंग वाले पाये गए। इसके साथ ही खाद के 737 नमूनों में से 11 घटिया मानक के पाये गए, जिसके चलते 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। इसके इलावा बीजों के 2113 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 49 गुणवत्ता मापदण्डों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बताया कि यह नमूने 1 अप्रैल, 2025 से अब तक लिए गए हैं और दोषी डीलरों और फर्मों के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डायरैक्टर ने आगे बताया कि कृषि विभाग ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पाँच फ्लाइंग स्क्वायड टीमें बनाईं हैं जिससे उनको उच्च– गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री प्रदान की जा सके। इस मीटिंग के दौरान राज्य में चल रही खरीफ फ़सल की बुवाई सम्बन्धी कामों का जायज़ा भी लिया गया।

# ग्राम चौपाल के माध्यम से मानकों के साथ खेतों तक – BIS हरियाणा की अनोखी पहल ग्राम मटौर (कैथल) में आयोजित

रमन कुमार

कैथल, भारतीय मानक ब्यूरो हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा आज ग्राम मटौर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को भारतीय मानकों के महत्व से जोड़ना है– विशेष रूप से कृषि और घरेलू जीवन में। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के सरपंच द्वारा स्वागत भाषण से हुई, जिसमें गुणवत्ता और ग्रामीण कल्याण पर चर्चा की नींव रखी गई। इसके

पश्चात, सुश्री आरती चौधरी, मानक संवर्धन अधिकारी, बीआईएस हरियाणा ने ग्राम चौपाल के उद्देश्य समझाए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सुरक्षा, अधिकारों और बिना जागरूकता के की जाने वाली खरीदारी से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता क्यों आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों को नकली या घटिया उत्पादों से निपटने और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके बाद, श्री सौरभ चंद्र, उप निदेशक एवं वैज्ञानिक–सी, बीआईएस हरियाणा ने भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमुख गतिविधियों जैसे मानकीकरण, प्रमाणन, हॉलमार्किंग और गुणवत्ता संवर्धन के बारे में बताया। उन्होंने कृषि एवं घरेलू उत्पादों से संबंधित महत्वपूर्ण मानकों की जानकारी दी, जिससे ग्रामीण यह समझ सकें कि कैसे ये मानक सुरक्षा, दक्षता और लागत में बचत में मदद करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं, किसानों, युवाओं और पंचायती राज प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

# नए भारत की नई कहानी, ग्रोथ मार्केट से ग्रोथ इंजन तक

लेखक – श्री गिरिराज सिंह,
वस्त्र मंत्री, भारत सरकार

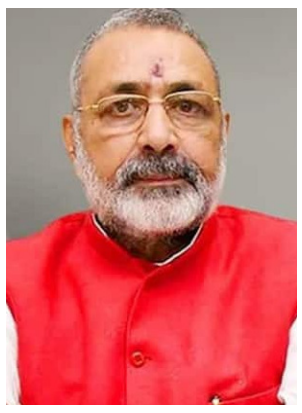



एक राष्ट्र की प्रगति केवल उसके आर्थिक सूचकांकों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस विकास से आम जनजीवन में कितनी गरिमा, अवसर और आत्मबल का संचार हुआ है। जब हम आज भारत की ओर देखते हैं, तो यह केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक जाग्रत समाज की तस्वीर है, जो आगे बढ़ना जानता है, जो अपने अतीत से सीखता है और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ रहा है। मेरे लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर, जो वित्त वर्ष 2024–25 की अंतिम तिमाही में 7.4ब्ल रही, एक आकंड़ा मात्र नहीं है। यह उस किसान की मेहनत का सम्मान है, जिसने आधुनिक तकनीक को अपनाकर पैदावार बढ़ाई। यह उस महिला उद्यमी की कहानी है, जिसने स्वयं सहायता समूह से यात्रा शुरू कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद दुनिया तक पहुंचाए। यह उस युवा इंजीनियर का आत्मविश्वास है, जिसने मेक इन इंडिया के अंतर्गत नौकरी ढूंढ़ने के बजाय नौकरी देने वाला बना। आज भारत की औसत विकास दर 6.5ब्ल है, और नॉमिनल जीडीपी 330 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। त्नस्क्ष संग्रह लगातार दो महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। यह आर्थिक आत्मबल अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गाँवों, छोटे कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचा है। डिजिटल क्रांति ने भारत के सामाजिक ताने–बाने में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। गाँव का एक युवा अब मोबाइल से भुगतान करता है, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में प्राप्त करता है और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से अपने सपनों को साकार करता है। आज क्तद्ध के जरिए 25 ट्रिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। यह डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का नया अध्याय है। भारत ने वैश्विक व्यापार में भी अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज की है। केवल अप्रैल 2025 में ही भारत से 3 मिलियन आईफोन द्वक्कद्धश्वह्द्ध एक्सपोर्ट हुए, चीन से तीन गुना ज़्यादा। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल बाज़ार नहीं, ग्लोबल वैल्यू चेन का प्रमुख स्तंभ बन चुका है। बीते दशक में भारत में 500 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है, जो इनोवेशन, रोज़गार और आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोल रहा है। हमारे किसान भी इस बदलाव के सशक्त भागीदार बने हैं। आज 51 मिलियन किसानों के पास डिजिटल किसान द्बष्ठ है, जिससे उन्हें उनकी भूमि, फसल और योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल मंडियाँ, और आत्मनिर्भर कृषि मिशन जैसे प्रयासों ने उन्हें सहयोगी नहीं, सहभागी बनाया है। भारत में गरीबी दर 2011–12 के 29.5ब्ल से घटकर आज 9.4ब्ल रह गई है। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का विस्तार है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अत्यंत गरीबी अब मात्र 5.3ब्ल रह गई है। इस परिवर्तन में उस ग्रामीण परिवार की कहानी छिपी है, जिसके बच्चे पहली बार स्कूल गए, जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को नज़दीक पाया, और जिसने आत्मनिर्भरता को अपनी पहचान बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। आज भारत एक साल में 1,600 इंजन बनाकर विश्व का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता है। ऊर्जा क्षेत्र में 49ब्ल क्षमता अब नवीकरणीय स्रोतों से है। भारत अब सस्टेनेबल विकास की राह पर तेज़ी से अग्रसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (द्ब) जैसे क्षेत्रों में भी भारत की क्षमता को वैश्विक मान्यता मिल रही है। ह्रश्वद्गठ्ठ जैसी संस्थाओं ने भारत में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय द्ब अकादमी शुरू की है, यह हमारे युवाओं की प्रतिभा और संभावनाओं में भरोसे का प्रमाण है। नए भारत की विकास यात्रा में टेक्सटाइल सेक्टर भी एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। तकनीकी वस्त्रों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (ह्रञ्जञ्जरू) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (क्रुद्ब) योजना एक–दूसरे के पूरक बनकर कार्य कर रही हैं। ह्रञ्जञ्जरू के तहत ?510 करोड़ की सहायता से 168 नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वहीं, टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों पर लाने के लिए देशभर में 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पूरी वैल्यू चेन को 'प्लग–एंड–प्ले' मॉडल पर काम करने की सुविधा मिलेगी। यह क्षेत्र अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार और निर्यात का नया प्रतीक बन चुका है। आज भारत को ढ्ढरूस्न और ढ्ढरूस्न जैसे वैश्विक संस्थान केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहे हैं। यह उस समर्पित प्रयास का परिणाम है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों, योजनाओं और नागरिकों की सहभागिता से संभव हुआ है। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि यह यात्रा केवल सरकार की नहीं, हर भारतीय की है। हमारे सामने आज जो उपलब्धियाँ हैं, वे उस संकल्प का परिणाम हैं जिसने हर गाँव, हर परिवार और हर नागरिक को जोड़ा। भारत आज एक विकल्प नहीं, एक प्रेरणा है, आत्मनिर्भरता की, समावेशिता की और वैश्विक नेतृत्व की। जब हम अमृतकाल में विकसित भारत @2047 की परिकल्पना करते हैं, तो वह केवल एक सपना नहीं, एक साझा संकल्प है और मुझे विश्वास है इस संकल्प की सिद्धि का समय अब दूर नहीं।

# कनिष्का पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तरुण चुग ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का किया आह्वान

## प्रवासी भारतीयों का योगदान अतुलनीय 7 मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बनी नये भारत की पहचान

मनदीप कौर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्का विमान) के 329 यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। चुग ने कहा कि यह घटना केवल भारत पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की अपील की जिसमें दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करना भारत की प्राथमिकता रही है। "आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, उससे सख्ती से निपटना चाहिए। आतंकवाद की फंडिंग तुरंत रोकी जानी चाहिए और इस खतरे को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए," उन्होंने कहा। आयरलैंड स्थित भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीयों एवं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए चुग ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी उल्लेख किया और इसे पाकिस्तान की द्बस्द्ब द्वारा शांति एवं विकास की प्रक्रिया को बाधित करने का कुप्रयास बताया। उन्होंने कहा कि "भारत को अस्थिर करने की साज़िशें बार–बार रची जाती हैं, लेकिन मोदी सरकार की निर्णायक नीति और देशवासियों की एकजुटता इन प्रयासों को हर बार नाकाम करती है।" इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" संकल्प पर भी चर्चा हुई। चुग ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उद्योग, सेवा, निर्यात जैसे क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति में विदेशों में बसे भारतीयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने हर भारतीय को वैश्विक मंचों पर सम्मान दिलाया है। आज भारत की उपस्थिति के बिना कोई भी वैश्विक मंच अधूरा समझा जाता है। भारत की विकास दर, स्थिर नेतृत्व और सक्रिय कूटनीति ने उसे वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। चुग ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वे भारत की सांस्कृतिक और विकासात्मक यात्रा के दूत बनें और देश के प्रति गर्व की भावना को नई पीढ़ी तक पहुँचाएं। उपस्थित कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने %विकसित भारत 2047% के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

# एनसीसी चंडीगढ़ ग्रुप द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले कैडेट्स का भव्य सम्मान समारोह आयोजित

कैप्टन सुभाष चंदर

चंडीगढ़, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, चंडीगढ़ द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी विश्व की सर्वोच्च चोटी को फतह करने वाले साहसी एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 2 चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी की अंडर ऑफिसर पद्मा नामग्याल, 1 हिमाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी की कैडेट कृतिका शर्मा तथा 2 आर एंड वी पंजाब स्क्वाड्रन एनसीसी की गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर अनामिका चौधरी को उनके असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के लिए सम्मानित किया गया। 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली इन कैडेट्स ने न केवल एनसीसी बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता मेजर जनरल जे.एस. चीमा, अतिरिक्त महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़) ने की। उनके साथ ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान, वाईएसएम, ग्रुप कमांडर, एनसीसी ग्रुप चंडीगढ़ भी उपस्थित रहे। इन जांबाज कैडेट्स को स्मृति चिह्न, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन पर्वतारोहियों की यात्रा केवल माउंट एवरेस्ट तक सीमित नहीं थी। यह अभियान माउंट आबी गामिन के प्री–एवरेस्ट अभियान से शुरू हुआ, जिसके बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) में बेसिक पर्वतारोहण प्रशिक्षण, सियाचिन ग्लेशियर में कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण, और फिर नेपाल के माउंट लबुचे पर चढ़ाई जैसे कठिन चरणों से होकर गुज़रा। हर एक चरण ने उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और तकनीकी दक्षता को निखारा। इनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इन्हें 10–सदस्यीय एनसीसी सीनियर डिवीजन/विंग एवरेस्ट अभियान दल में चयनित किया गया, जिसने 3 अप्रैल से 18 मई 2025 के बीच एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। यह चयन एक अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया और गहन प्रशिक्षण के बाद हुआ था। इनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सराहा, जिसमें वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विशेष सम्मान समारोह भी शामिल है। इन बहादुर कैडेट्स की सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत साहस का प्रमाण है, बल्कि यह पूरे देश के युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि अनुशासन, समर्पण और अटूट जज़्बे के साथ कोई भी शिखर अजेय नहीं होता।

# पंजाब सरकार द्वारा तरनतारन में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 5.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत - डॉ. बलजीत कौर

## पंजाब के 17 जिलों में पहले ही बन चुके हैं अंबेडकर भवन, 5 अन्य जिलों में जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

एसके सक्सैना

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, तरनतारन जिले में बनाए जा रहे डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 5.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी समाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि यह राशि चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत की गई है, जो जल्द ही लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग्स) के मुख्य अभियंता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि भवन निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि तरनतारन में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए कुल 5.93 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 60 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और शेष 5.33 करोड़ रुपये जल्द ही लोक निर्माण विभाग के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार भवन के निर्माण पर कुल 5.93 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने यह भी बताया कि तरनतारन में डॉ. अंबेडकर भवन की चारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के 17 जिलों में डॉ. अंबेडकर भवन पहले ही बन चुके हैं, जहां एक ही छत के नीचे शोषित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सिंगल विंडो के माध्यम से विभिन्न सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शेष 5 जिलों – एस.ए.एस. नगर, बरनाला, फाजिल्का, पठानकोट और मलोट (मलेरकोटला) में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तरनतारन में बन रहे डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता, पूरी पारदर्शिता और निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि इलाके के लोगों को जल्द से जल्द इस भवन की सुविधा मिल सके।

# कमिश्नरेट जालंधर पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थानों पर केंद्रित केसो अभियान चलाया

रमन कुमार

जालंधर, चल रहे युद्ध नशे के विरुद्ध ' पहल के हिस्से के रूप में, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने सिटी जोन–1, जालंधर में कई प्रमुख स्थानों पर एक केंद्रित केसो अभियान चलाया, जिसमें विशेष रूप से आपराधिक तत्वों और ड्रग तस्करी नेटवर्क के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस कमिश्नर, धनप्रीत कौर ने कहा कि यह अभियान डीसीपी (जांच), श्री मनप्रीत सिंह ढिल्लों और एडीसीपी–1, सुश्री आकर्षि जैन की देखरेख में संबंधित एसीपी द्वारा रणनीतिक तालमेल के साथ चलाया गया। एक व्यापक और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए सिटी जोन–1 डिवीजन की पुलिस टीमों को जुटाया गया था। इस अभियान में ज्ञात ड्रग हॉटस्पॉट, विशेष रूप से तस्करों द्वारा ट्रांजिट प्वाइंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों पर सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध छापे शामिल थे। संदिग्धों के घरों और आस–पास के परिसरों की गहन तलाशी ली गई। छिपे हुए प्रतिबंधित पदार्थ, विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तलाशी पर विशेष ध्यान दिया गया। कानूनी अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक आईडी जांच के माध्यम से निवासियों की पहचान की पुष्टि सख्ती से की गई। किसी भी चल रही अवैध गतिविधि की जांच के लिए खाली और निर्जन क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। यह पहल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीपी जालंधर ने जोर देकर कहा कि जालंधर को एक सुरक्षित और नशा मुक्त शहर बनाने के निरंतर प्रयासों के तहत भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

# पुरी, चुग समेत भारतीय शिष्टमंडल ने दी कनिष्क ब्लास्ट के शहीदों को श्रधांजलि

## आतंकवाद मानवता के विरुद्ध अपराध है, भारत का संकल्प है आतंकवाद का समूल विनाश –चुग

मनदीप कौर

कॉर्क, आयरलैंड/ चंडीगढ़ – भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आज आयरलैंड के कॉर्क स्थित अहकिस्ता स्मारक पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 %कानिष्का% बम ब्लास्ट की 40वीं बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। यह भारतीय शिष्टमंडल भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में पहुंचा, जिसमें देश के पाँच राज्यों के विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस समारोह में आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन, कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंदसंगरी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर तरुण चुग ने कहा, "यह हादसा न केवल भारत के लिए, बल्कि समूची मानवता के लिए गहरा आघात था। यह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आतंकवाद किसी एक देश या समुदाय का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध %जीरो टॉलरेंस% की नीति अपनाई है और भारत आतंकवाद के समूल नाश के लिए कटिबद्ध है। "पीड़ितों के परिजनों का दर्द आज भी उतना ही जीवित है। उनकी आंखों में आज भी वही पीड़ा और आंसू हैं। हम यहां आए हैं यह संदेश देने कि भारत उनकी पीड़ा में सहभागी है और सदैव उनके साथ खड़ा है।

# रस्ता मोहल्ला मे धर्म एकता क्लब के नौजवानों ने खून दान कैम्प लगाया

एसके सक्सैना

जालंधर, नार्थ विधानसभा के रस्ता मोहल्ला क्षेत्र मे धर्म एकता क्लब के नौजवानों द्वारा पहला रक्तदान शिवर लगाया गया।जिसमे दो दर्जन से ज़्यादा नौजवानों ने खूनदान किया।इस शिवर मे मुख्य रूप से भाजपा जालंधर के महामंत्री अशोक सरीन हिक्की मुख्य रूप से शामिल हुए।इस अवसर पर अशोक सरीन हिक्की ने पहला रक्तदान शिवर लगा नई शुरुआत करने वाले क्लब के नौजवानों को बधाई देते हुए कहा अच्छे संस्कारों की बदौलत युवाओं मे रक्तदान करने की सोच आती है।क्युकी आज के नौजवान मे नशों के बढ़ते चलन की वजह से युवा पीढ़ी का भविष्य ख़राब हो रहा है।वही आज धर्म एकता मंच के नौजवानों ने पहला रक्तदान कैम्प लगाके बाकी युवा पीढ़ी को भी संदेश दिया है।इसलिए यह सब नौजवान बधाई के पात्र है।सरीन ने बताया क्लब के नौजवानों ने विश्वास दिलाया की भविष्य मे यह सब नौजवान एकजुट होकर निरंतर युवाओ को नशों से बचाने के लिए जागरूक करने हेतु नशा विरोधी कार्यक्रम करवायेंगे ताकि रस्ता मोहल्ला समेत आसपास के इलाकों के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण के काम पर लगाया जायेगा।इस मौके पर क्लब के सदस्य शुभम अटवाल, शिवम अटवाल, प्रिंस, अजय, सर्वेश, अनुज शारदा, समीर, सुमित, रोहित, जसकरन, विशाल, संजीव, सुनील आदि हाज़रि थे।

**अच्छे संस्कारों की बदौलत युवाओं मे रक्तदान करने की सोच आती है–अशोक सरीन हिक्की**

# कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने किया लम्मे से संधमा लिंक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ

**25 वर्षों की प्रतीक्षा हुई पूरी, 51 लाख की लागत से बनेगी 1.30 किलोमीटर पक्की सड़क**

मनदीप कौर

होशियारपुर, शामचौरासी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने गांव लम्मे से गांव संधमा को जोड़ने वाली लिंक सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। यह सड़क लगभग 1.30 किलोमीटर लंबी होगी और इसके निर्माण पर कुल 51 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अधूरी पड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सड़क वर्षों से कच्ची थी और बरसात के मौसम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यह सड़क पक्की बनने से आवागमन तो सुगम होगा ही, साथ ही व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लिंक सड़क दो ज़िलों को जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे क्षेत्रीय तालमेल और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिलेगी। यह परियोजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गांववासियों ने सड़क निर्माण की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों से यह सड़क उपेक्षित रही, जिससे ग्रामीण विकास की रफ्तार थमी हुई थी। अब इस पहल से बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक ले जाने में सुविधा होगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के सभी गांवों तक पक्की सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ग्रामीण जनता को बेहतर जीवनस्तर मिल सके। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इस मौके पर परमिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह, भूपिंदरपाल सिंह और मास्टर अमरजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, कुलविंदर कौर के अलावा अन्य गणमान्य भी मौजूद थे।

# कुलतार सिंह संधवां ने विद्यार्थियों को राजनीति में रुचि लेने और स्वयं राजनीति करने के लिए किया प्रेरित

**पंजाब के 35 कॉलेजों के 100 से अधिक विद्यार्थियों से मिले स्पीकर एवं विधायक, विद्यार्थियों को अपने सपने ऊंचे रखने चाहिए, और वही लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, जिनके सपने ऊंचे होते हैं- कुलतार सिंह संधवां**

एसके सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने आज पंजाब के 35 कॉलेजों से आए 100 से अधिक विद्यार्थियों और प्रोफेसरों से मुलाकात की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्पीकर से उनकी जिम्मेदारियों, विधानसभा की कार्यवाही और राजनीतिक दबावों से निपटने के तरीकों पर प्रश्न पूछे। स्पीकर ने बताया कि वे विपक्ष को बराबर बोलने का अवसर देते हैं। स्पीकर संधवां ने कहा कि राजनीति वास्तव में जनसेवा है और हमें अपनी कौम की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। जब विद्यार्थियों ने सदन की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपने-अपने कार्य ईमानदारी से करें तो सदन की कार्यवाही और अधिक पारदर्शी हो सकती है। उन्होंने बताया कि वे 2022 से विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करवा रहे हैं ताकि आम जनता भी इसे सुन सके और सदन की गतिविधियों से अवगत हो सके। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे भी सदन की कार्यवाही देखें और अपने क्षेत्र के विधायक से यह अवश्य पूछें कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए क्या कार्य और कानून बनाए हैं। जब विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा की बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाया तो स्पीकर ने कहा कि शिक्षा सभी को निःशुल्क मिलनी चाहिए और वे इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन करेंगे कि उच्च शिक्षा को निःशुल्क करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा अपनाने के साथ अन्य भाषाएं भी सीखने की सलाह दी। स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्यवाही में वे हर जनप्रतिनिधि को समान अवसर देते हैं ताकि हर सदस्य अपनी बात रख सके। जब विद्यार्थियों ने पूछा कि चुनावी टिकट पाने के लिए तो बड़ी पार्टियों को लाखों रुपये देने पड़ते हैं, इस पर उन्होंने बताया कि वे स्वयं गांव के सरपंच थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें बिना कोई पैसे लिए टिकट दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो पार्टी स्वयं आपको टिकट देगी। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति जनता की सेवा है और हमें आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को रोजाना एक शब्द गुरबानी पढ़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पंजाब को और आगे बढ़ाना है तो उद्योगों को पंजाब में विकसित करना होगा। कृषि को भी एग्री बिजनेस के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि पंजाब की भूमि बहुत उपजाऊ है और ऐसी भूमि मिलना बहुत कठिन है। स्पीकर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे बड़े सपने देखें क्योंकि बड़े सपने देखने वाले ही अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में तनाव न लें और खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करें। उन्होंने विद्यार्थियों को सदन में लेकर गए, उन्हें सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी और उनके साथ एक डिबेट भी करवाई ताकि विद्यार्थियों की राजनीति में रुचि और बढ़े। इस मुलाकात में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने स्पीकर को एक शॉल, एक विरासती हाथ वाला पंखा और एक सीनरी भेंट की।

# 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ब्लॉक समिति पटवारी विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुरदासपुर में तैनात ब्लॉक समिति पटवारी निशान सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी गुरदासपुर के गांव बबरी नंगल की एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता, जो ग्राम पंचायत बबरी नंगल की मौजूदा पंचायत सदस्य है, ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि उसके पति पिछले 50 वर्षों से गांव की साझा (शामलात) 25 एकड़ जमीन में से लगभग 22 कनाल और 11 मरले भूमि पर खेती कर रहे हैं और यह ज़मीन उनके नाम पर गिरदावरी में दर्ज भी है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि एक शिकायत के आधार पर, बीडीपीओ कार्यालय ने उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा था। उन्होंने गांव के मौजूदा सरपंच से इस मामले को सुलझाने के लिए निवेदन किया, लेकिन पटवारी निशान सिंह ने विभागीय स्तर पर मामला हल करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी निशान सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना, अमृतसर रेंज में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे जांच जारी है।

# श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए-स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला

**स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) ने पठानकोट में पुलिस, सेना, सिविल प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता**

पंकज

चंडीगढ़/पठानकोट, श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा व्यापक, बहुस्तरीय और अंतर-एजेंसी सुरक्षा एवं समन्वय योजना लागू की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु उन्नत निगरानी, बलों की रणनीतिक तैनाती और 24 घंटे समन्वय सुनिश्चित किया गया है। यह जानकारी आज स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) श्री अर्पित शुक्ला ने दी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस वार्षिक यात्रा में देशभर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें से कई श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र गुफा जाने के लिए विशेष रूप से पंजाब के पठानकोट जिले से होकर गुजरते हैं। स्पेशल डीजीपी ने वार्षिक तीर्थ यात्रा हेतु सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सेना, सिविल प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा एवं समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। पठानकोट में आयोजित इस बैठक के दौरान अमरनाथ यात्रा से जुड़े रणनीतिक प्रबंधों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा प्रबंध, यातायात व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पठानकोट की रणनीतिक स्थिति, जो पाकिस्तान के साथ 26.385 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और जहां महत्वपूर्ण रक्षा इकाइयां स्थित हैं, को देखते हुए सुरक्षा में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को और मजबूत करते हुए जम्मू एवं कश्मीर की ओर जाने वाली सभी सड़कों की जिम्मेदारी कमांडेंट स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि कमांडेंट रैंक के अधिकारियों की निगरानी में यात्रा मार्ग को सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि 24 घंटे जमीनी स्तर पर निगरानी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि नाका माधोपुर में 24 घंटे संचालित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसकी निगरानी एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है, जो उन्नत निगरानी प्रणालियों के माध्यम से सभी वाहनों और श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि संभावित खतरों की पहचान और उन्हें समय रहते रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, लंगर स्थलों, धार्मिक स्थलों और पूरे यात्रा मार्ग सहित संवेदनशील स्थानों पर प्रतिदिन एंटी-सबोटाज और सुरक्षा जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दलजिंदर सिंह ढिल्लों की निगरानी में सुरक्षा प्रबंध लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए मोबाइल निगरानी यूनिट, हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन आधारित हवाई निगरानी, जीपीएस समर्थित गश्त और रियल-टाइम रिपोर्टिंग प्रणाली जैसे अतिरिक्त तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग के पेट्रोल पंप, ढाबा, होटल, गेस्ट हाउस और सड़क किनारे स्थित अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों एवं स्टाफ को विशेष जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे किसी भी असामान्य गतिविधि, संदिग्ध वस्तु या अज्ञात व्यक्ति की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को दे सकें। इस बैठक में डीआईजी बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह, एआईजी सुखमिंदर सिंह मान, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट आदित्य उप्पल, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर कठुआ डॉ. राकेश मिन्हास, एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों, एसएसपी होशियारपुर संदीप कुमार मलिक, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, तथा पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पुलिस एवं सिविल अधिकारी भी उपस्थित थे।

# पंजाब पुलिस द्वारा 151 नशा तस्कर गिरफ़्तार; 533 ग्राम हेरोइन, 2.8 किलो अफ़ीम और 5.3 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद

कैप्टन सुभाष चंदर

चंडीगढ़, राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरु किये गए ''युद्ध नशों विरुद्ध'' के 110वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 151 नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े में से 533 ग्राम हेरोइन, 2.8 किलो अफ़ीम और 5.32 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इससे सिर्फ़ 113 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 18,719 हो गई है। यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया। ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और एस. एस. पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है। आपरेशन के विवरण देते हुये स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 99 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के सम्मिलन वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 523 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 98 ऐफआईआरज़ दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 502 शक्की व्यक्तियों की जांच भी की। स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 54 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।

# वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा बड़ी कार्यवाही, आबकारी और कर विभाग की औचक चैकिंग

**कई ब्रांचों का रिकार्ड लिया कब्ज़े में, तुरंत दिशा-निर्देश भी जारी, फाइलों का निपटारा करने में की देरी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा**

मनदीप कौर

चंडीगढ़/पटियाला, पंजाब के वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पटियाला में आबकारी और कर विभाग के मुख्य दफ़्तर में औचक चैकिंग की। मंगलवार दोपहर के खाने के तुरंत बाद पटियाला पहुँचे हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी कमिश्नर के साथ आबकारी और कर विभाग के मुख्य दफ़्तर में औचक चैकिंग करते हुये विभिन्न ब्रांचों में जाकर जायज़ा लिया और यहाँ तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की हाज़िरी जांचने के साथ-साथ उनके मेज़ों पर पड़ी फाइलों की भी जांच की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी यह चैकिंग विशेषतः कई फाइलों और मामलों का निपटारा करने में हो रही देरी का कारण जानना है। इस दौरान वित्त मंत्री और कमिश्नर एक्साईज विभाग ने कई तरह के दस्तावेज़ अपने कब्ज़े में लिए और कईयों की सूची बना कर आगे कार्यवाही के लिए आदेश दिए। सरकारी दसतावेज़ी फाइलों के साथ साथ उन्होंने एक्साईज विभाग में चल रहे कामकाज जिसमें ई आफिस मुख्य रूप से शामिल है, की भी जांच की और यह देखने की कोशिश की कि एक केस या फाइल निपटाने में कितनी देरी हो रही है और क्या यह काम तुरंत हो रहे हैं जा एक दो दिन की कोताही भी इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि काम करने या फाइल निपटाने में देरी भी भ्रष्टाचार माना जायेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने अलग अलग ब्रांचों के सुपरडैंट और अन्य अधिकारियों को भी तलब किया और जो अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे, उनकी हाज़िरी भी जांची और जो अधिकारी बिना मूवमैंट रजिस्टर भरे अपने डैपूटेशन वाले स्थान पर गए हुए थे, उनकी भी

पड़ताल की। इसके उपरांत मीडिया के साथ बातचीत करते हुये वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति काम में देरी करता है तो वह भी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नैगटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव रिपोर्ट देनी उस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है लेकिन काम में किसी भी तरह की जानबुझ कर की गयी देरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आबकारी मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी बिना मूवमैंट रजिस्टर भरे दफ़्तर में मौजूद नहीं है उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाऐगी। उन्होंने बताया कि कुछ ब्रांचों का रिकार्ड कब्ज़े में लिया गया है और कुछ अधिकारियों की पड़ताल करने के लिए कह दिया गया है। एक सवाल के जवाब में हरपाल चीमा ने कहा कि हाईवे पर जो कमर्शियल वाहन चल रहे हैं ख़ास तौर पर भारी वाहन, जिनकी तरफ से जीएसटी की चोरी की जाती है या किसी अन्य तरह की कर सम्बन्धी कोताही की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ पहले भी कार्यवाही की गई थी और आगे भी इस तरह की कार्यवाही की जाऐगी। एडवोकेट चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जिन मुद्दों पर पंजाब की सत्ता में आई थी, उन सभी मुद्दों का हल किया जायेगा और लोगों को एक पारदर्शी और इमानदार सरकार देने के साथ साथ समयबद्ध तरीके के साथ उनके काम भी किये जाएंगे। इस मौके पर उनके साथ आबकारी और कर कमिश्नर जतिन्दर जोरवाल, डायरैक्टर इन्वेस्टिगेशन जसकरण सिंह बराड़, अतिरिक्त डायरैक्टर ऐक्साइज एंड टैक्सेशन गुरप्रीत सिंह, ए. आई. जी. सुखमिन्दर सिंह चौहान और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।